बैंकों का मायाजाल
रवि कोहाड़
I PROMISE TO
AY THE BEARER
SUM OF ONE
AND RUPEES

बैंकों का मायाजाल

रवि कोहाड़

बैंकों का मायाजाल

BANKON KA MAYAJAL

रवि कोहाड़

मूल्यः अनमोल

सहयोग राशिः श्रद्धा अनुसार

प्रकाशकः **युवा क्रान्ति**

746, द्वितीय तल, निकट जैन चैरिटेबल डिस्पेंसरी

चिराग दिल्ली, दिल्ली - 110017

08745026277

ई-मेलः yuvakranti.org@gmail.com

वेबसाइटः www.yuvakranti.org

www.BankJaal.com

युवा क्रान्ति

युवा क्रान्ति उन नौजवानों का संगठन है जो जनान्दोलनों में अपनी पढ़ाई और कामकाज को छोड़कर शामिल हुए, किन्तु ये आन्दोलन युवाओं के आक्रोश को दिशा देने और उनके सपनों को पूरा करने में असफल रहे। तब हमने स्वयं भारतीय राष्ट्रवाद के विविध स्वरों को साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया।

मित्रों, लाखों भारतवासियों ने जिस आज़ादी के लिए शहादतें दी, उनके सपनों का स्वतंत्र, स्वावलम्बी और स्वाभिमानी भारत आज तक नहीं बन सका। योग्य नेतृत्व के अभाव और दूरदर्शिता की कमी के कारण आज राष्ट्र में चारों तरफ गरीबी, शोषण, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, गैर-बराबरी, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, आतंकवाद जैसी तमाम समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हैं। निराशा के बढ़ते बादलों को छाँटने तथा शान्ति, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए हम युवाओं ने वैचारिक और संघर्षशील नौजवान साथियों का एक राष्ट्रीय संगठन बनाने का निर्णय लिया।

तो साथियों आओ, इस चुनौती को स्वीकार करें। युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा गठित युवा संगठन युवा क्रान्ति के माध्यम से हम सब मिलकर राष्ट्र और समाज की चुनौतियों को समझें और उनका हल निकालने की कोशिश करें।

अन्ततः शहीदों के सपनों का भारत निर्मित करना हम राष्ट्रवादी युवाओं का दायित्व है। इसलिए हम 30 साल के कम उम्र के नौजवान एकताबद्ध हुए हैं। स्वतंत्र, स्वावलम्बी और स्वाभिमानी भारत का निर्माण हम सब मिलकर करें - यह सपना और विश्वास हमेशा हमारा पथ प्रदर्शन करेगा।

लेखक परिचय

रवि कोहाड़ का जन्म 13 मार्च, 1989 को, गाँव छिनौली, ज़िला सोनीपत (हरियाणा) में हुआ। बचपन से ही चिन्तनशील रवि ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), दिल्ली से बी.टेक. किया, लेकिन देश और समाज के लिए कुछ करने का जज़्बा उन्हें आन्दोलनों की ओर खींच लाया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को बहुत नज़दीक से देखा और बाबा रामदेव के कालाधन वापसी अभियान में शामिल रहे। अन्ना हज़ारे के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। देश के कई विद्वानों से संवाद, विचार-विमर्श किया। युवा क्रान्ति के संस्थापक संयोजक।

दो शब्द

किशोरावस्था से ही अपने आसपास हर तरह की विषमता, गरीबी, युद्ध और अपराध देखते हुए मैं सोचा करता था कि यह सब क्यों है? क्या इसे हमेशा-हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता? इस पर गौर करना शुरू किया तो पाया कि अनेक समाजसेवी, शासकीय कर्मचारी, राजनेता, आन्दोलनकारी, बुद्धिजीवी आदि ईमानदार और समर्पित लोग इन तमाम समस्याओं को अपने-अपने तरीके-से पहचानने और उनका हल खोजने में दिलोजान से जुटे हुए हैं। लेकिन फिर भी समस्याएँ खत्म होना तो दूर, बढ़ती ही जा रही हैं....।

जब उच्च शिक्षा के लिए मैं भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), दिल्ली में दाखिल हुआ तो वहाँ इंजिनीयरिंग के बदले मेरा ध्यान अर्थव्यवस्था और समाज के अध्ययन में लग गया। एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। कई किताबें पढ़ीं, बहुत सोचा और कई लोगों से मिला। इस प्रक्रिया से समझ आने लगा कि हमें अपने आसपास नजर आने वाली समस्याएँ दरअसल एक विशाल राक्षस की तरह हैं। उस राक्षस का आकार इतना बड़ा है कि अक्सर हम उसका कोई एक-आध अंग ही देख और छू पाते हैं। समाज को खुशहाल बनाने के लिए इस राक्षस रूपी समस्या से जूझने वाले तमाम सज्जन उस एक अंग को ही सम्पूर्ण राक्षस मान बैठे हैं और उससे लगातार जूझते हुए अपनी ऊर्जा गँवाते जा रहे हैं।

अपने अध्ययन में मैंने पाया कि असल में समस्या जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, अकाल, संसाधनों की कमी, पर्यावरण असन्तुलन, भ्रष्टाचार, काला धन आदि की न होकर इस पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल, यानी मुद्रा व्यवस्था (करेंसी सिस्टम) में है। यह एक ऐसा जटिल लेकिन खोखला ताना-बाना है जिसे बूझ पाना यूँ तो बहुत सरल है, लेकिन पता नहीं क्यों यह अनेक विद्वानों, समाज सेवकों, आन्दोलकारियों आदि के लिए अबूझ बना हुआ है।

मुद्रा का चलन एक शोषणकारी सोच की परिणति है, जिसके जरिए शातिर पूँजीवादी मेहनतकश लोगों का श्रम, प्राकृतिक संसाधन, तमाम तरह के उत्पाद, और यहाँ तक कि हमारी सोच-समझ और बुद्धि को भी खरीद लेते है। आभासी समृद्धि का एक ऐसा

मायाजाल इस मुद्रा व्यवस्था के जरिए खड़ा होता है जिसे पाने के लिए दुनिया के करोड़ों-अरबों लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन न तो अपने जीवन को और न ही अपने समाज या देश को खुशहाल बना पाते हैं। अपनी इस पुस्तक के माध्यम से मैं इस दुष्चक्र को आपके सामने रखने का एक विनम्र प्रयास कर रहा हूँ।

लेकिन, इससे पहले मैंने अपनी इस समझ को देश के अनेक प्रसिद्ध सज्जनों के सामने रखने की कोशिश की थी। कुछ लोगों तक तो मैं पहुँच ही न पाया। मेरा सौभाग्य है कि अण्णा हजारे, बाबा रामदेव, अरविन्द केजरीवाल और अन्य कई सामाजिक और राजनैतिक नेताओं से मेरा संवाद हो सका। मैंने अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बताया कि लोकपाल कानून, काला धन वापसी, भ्रष्टाचार से मुक्ति आदि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हम इस अर्थव्यवस्था के मर्म, यानी मुद्रा व्यवस्था पर चोट न करे। इस संवाद के नतीजे के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उन्हें बात कुछ-कुछ समझ आई और कुछ-कुछ नहीं।

अन्ततः मैंने फैसला किया कि देश के युवा साथियों के बीच से एक नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत है जो सीधे इस व्यवस्था को चुनौती देने का हौसला करें। इस क्रम में मुझे कुछ वरिष्ठ साथी मिले, जो इस बात को समझते थे और साथ चलने को तैयार थे। इसमें राकेश रफीक और अक्षय भाई का विशेष योगदान मिला। इस तरह युवा क्रान्ति का जन्म हुआ। इस पुस्तक को इस स्वरूप तक पहुँचाने में मेरे माता-पिता का आशीर्वाद और कुछ हमउम्र साथियों का सहयोग मिला जिसमें हिमांशु तिवारी, प्रताप चौधरी और संजय सामाजिक प्रमुख हैं।

मैं एक साधारण नौजवान हूँ जो इस पुस्तिका से माध्यम से वो सच आपसे साझा करना चाहता हूँ जिसे मैंने अपने अध्ययन और अनुभव से महसूस किया है। अगर आप देश और दुनिया का भला चाहते हैं तो आपसे यह विनम्र अपेक्षा है कि कुछ समय निकालकर इस पुस्तिका को पढ़ें। अपनी राय से मुझे अवगत भी कराएँ ताकि कोई कमी हो तो मैं पूरी कर सकूँ, कोई सवाल हो तो उसका जवाब देने या खोजने की कोशिश कर सकूँ।

अगर आपके दिल की भी वही आवाज है जो मेरे दिल की, तो आओ, हम कन्धे से कन्धा मिला कर आगे बढ़ें और व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष को आगे बढ़ाएँ।

रवि कोहाड़

प्रस्तावना

आज भारत की सवा सौ करोड़ जनता और पूरी दुनिया की कुल तकरीबन सात सौ करोड़ की आबादी जिस भयावह स्थिति से गुज़र रही है उस स्थिति को अनुभव करते हुए कोई भी जागृत व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। आज पूरा विश्व गरीबी, बेरोज़गारी, शोषण, आर्थिक विषमता से लेकर हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसी संवेदनशील समस्याओं से गुज़रते हुए विनाश की कगार पर खड़ा है। दुनिया में हर रोज़ तकरीबन 34 हज़ार बच्चे भूख और कुपोषण से मर रहे हैं और लगभग 100 करोड़ लोग रोज़ भूखे सो रहे हैं। हिंसा, युद्ध और आतंकवाद की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गँवाते हैं। अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो प्रतिवर्ष तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बेरोज़गारों की फौज तैयार हो रही है।

शोषण और आर्थिक विषमता की बात की जाए तो पूरी दुनिया के 7 प्रतिशत लोगों का 85 प्रतिशत संसाधनों पर कब्ज़ा है और भारत में तो लगभग 100 पूँजीपतियों के पास देश के 52 प्रतिशत संसाधन मौजूद हैं। जल, जंगल, ज़मीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कार्पोरेट घरानों का कब्ज़ा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ किसान, आदिवासी और दलित जैसे हाशिए के लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर उनसे जल, जंगल और ज़मीन छीने जा रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक असहिष्णुता, नारी उत्पीडन, नैतिक अधोपतन अपनी सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं।

दुनिया की बुनियादी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं को सामन्तवाद और पूँजीवाद से लेकर साम्यवाद और समाजवाद तक का सारा ढाँचा सुलझाने में असमर्थ रहा है।

इन सभी समस्याओं को लेकर अपने देश समेत पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक लोगों ने विविध प्रयास किए, जो अब भी जारी हैं; मगर सारे प्रयास कुछ सीमा तक पहुँच कर समाप्त हो जाते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं। रूसो से लेकर टॉलस्टाय और मार्क्स से लेकर गाँधी तक जितनी भी विचारधाराओं का प्रयास चल रहा है, सारे प्रयास एक सीमा में बँध से गए हैं। भारत में आज़ादी के बाद आचार्य विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और आज के

समय में अण्णा हजारे द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रयास एक कदम आगे बढ़ने के बाद रास्ते में कहीं खो गए। सवाल इस बात का है कि इन तमाम ईमानदार प्रयासों में कमी कहाँ रह जाती है। क्या व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में, रणनीति में, व्यक्तित्व में या इन तीनो में ही?

इस पुस्तिका में व्यवस्था के विश्लेषण में रह गई कमी को दूर करने की कोशिश की गई है। शरीर के ऊपरी हिस्से में दिखाई देने वाला फोड़ा रोग का लक्षण हो सकता है, मगर रोग का कारण नहीं। ऐसे ही देश और दुनिया में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार इत्यादि समाज के रोग के लक्षण हैं, कारण नहीं। असली कारण तो विनिमय अर्थशास्त्र के आधार पर खड़ा वित्तीय पूँजी का संस्थान है। अर्थशास्त्र का दार्शनिक आधार 'विनिमय' है जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच के सतत व सन्तुलित सम्बन्ध को विखण्डित कर देता है। वित्तीय पूँजी की इमारत का ढाँचा इतना जटिल है कि इसे समझने के लिए बड़े से बड़े अर्थशास्त्री का दिमाग भी चकरा जाता है और इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े क्रान्तिकारियों का सामर्थ्य भी बौना साबित होता है। वित्तीय पूँजी के खेल को समझकर जिन गिने-चुने राष्ट्रनेताओं ने कदम उठाने का साहस किया, उनको खत्म करके उनके सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया गया।

इस पुस्तिका में वित्तीय पूँजी की तकनीकी कार्यान्वन की सारी जटिल प्रक्रियाओं का खुलासा किया गया है जो इस पुस्तिका का सार है।

अक्षय कुमार
संगठक,
युवा क्रान्ति

विषय सूची

1

किसकी दुनिया?

किसका शासन?

किसका पैसा?

तीन यक्ष प्रश्न हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जिनको समझे बिना व्यवस्था परिवर्तन एक असम्भव चुनौती है।

- दुनिया पर कौन शासन करता है?
- दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, युद्ध इत्यादि क्यों है?
- दुनिया का हर देश और लगभग सभी व्यक्ति कर्ज में है तो यह कर्ज है किसका? पैसा क्या है और कर्ज देने के लिए इसे बनाता/छापता कौन है?

2
बदल गए गुलामी के तरीके

हम कभी अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, बस शासन करने के तरीके बदल गए और हमने आज़ादी का भ्रम पाल लिया। यह याद रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले वे लोग गुलाम बनते हैं जिनको ये भ्रम हो जाता है कि वे आज़ाद हैं।

1862 में ब्रिटिश बैंकिंग द्वारा अमेरिकी बैंकर्स के लिए एक सुझाव - **"मैं और मेरे यूरोपियन मित्रों को यह जानकर ख़ुशी हुई कि गृहयुद्ध के बाद अमेरिका में जातिगत गुलामी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मालिक को गुलामों कि सारी ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं। जबकि सबसे सरल तरीका यह है कि पूँजी द्वारा लोगों की आमदनी नियंत्रित करके उनको नियंत्रित किया जाए। और यह सब किया जा सकता है पैसे को नियंत्रित करके।"**

दिखाए गए पिरामिड में शीर्ष पर विश्व के शासक विराजमान हैं और बिल्कुल नीचे शोषित जनता है, जो निरन्तर अभाव में जी रही है। जनता पर नियंत्रण के लिए दुनिया के हर देश में सरकारें विराजमान हैं, जो आम तौर पर जनता के हित में नहीं बल्कि विश्व के शासकों के लिए काम करती हैं। मीडिया और शिक्षा व्यवस्था सरकार के सहयोग से विश्व के शासकों के पक्ष में लोगो का मानस निर्माण (मानसिक गुलामी) का काम करती है। शोषण के विरोध में खड़े लोगों का दमन करने के लिए खुफिया संस्थाएं, सेना, पुलिस, कोर्ट, जेल इत्यादि की व्यवस्था बना रखी है। सरकारों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बैठी हैं जो विश्व के सभी संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। अधिकतर लोगों को यह लगता है की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ही स्वतंत्र रूप से विश्व को चलाती हैं। लेकिन इनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था है, जो सही मायने में विश्व का आर्थिक नियंत्रण करते हुए शासकों के साम्राज्य को बनाए हुए है। यह नियंत्रण ब्याज, कर (टैक्स) राजस्व, केन्द्रीय बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसी संस्थाओं के माध्यम से होता है।

व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोग किसी कानून में परिवर्तन चाहते हैं और दलील देते हैं कि सख्त से सख्त कानून बना देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा;
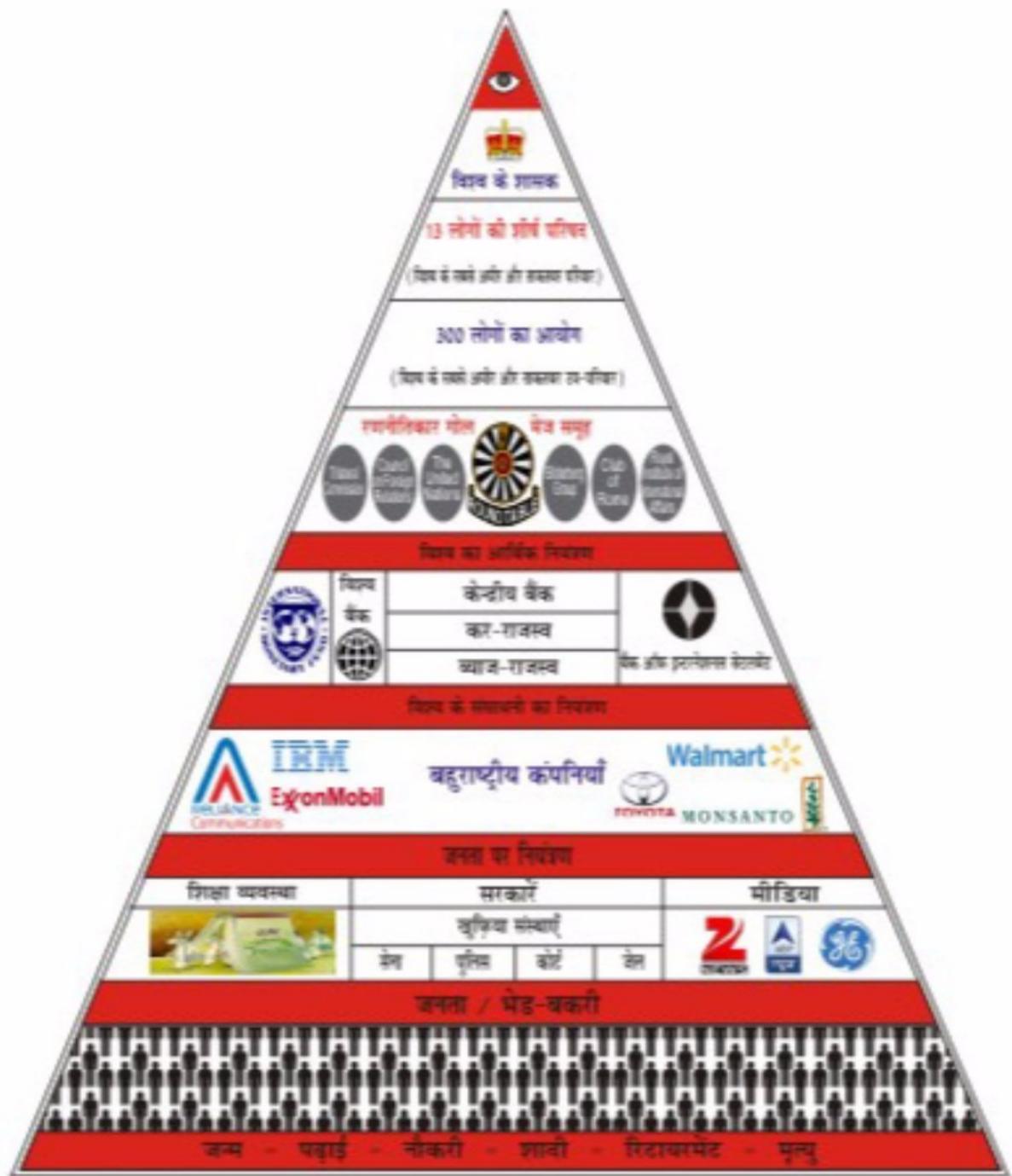
जबकि वे लोग यह नहीं जानते की व्यवस्था का ढाँचा कुछ और ही है और सरकारें स्वतंत्र नहीं हैं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों ने एक रणनीतिकार समूह बनाया हुआ है, जो षड्यंत्रकारी ढंग से छिपकर विश्व की दशा और दिशा तय करते हैं। इसके ऊपर 300 लोगों का एक आयोग बना हुआ है जो विश्व के सबसे अमीर और ताकतवर उप-परिवार है। इनके ऊपर 13 लोगों की शीर्ष परिषद है जो विश्व के सबसे ताकतवर परिवार हैं, जो विश्व के शासकों के मंत्री के रूप में काम करते हैं और ये सभी अपना एक-एक प्रतिनिधि लन्दन शहर के पार्षद के रूप में नियुक्त करते हैं। इन 13 लोगों के आयोग में रोथशिल्ड परिवार, रॉकफेलर परिवार, मोरगन परिवार, स्किफ परिवार प्रमुख हैं।

हेनरी फोर्ड

प्रसिद्ध फोर्ड कम्पनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने इस व्यवस्था के बारे में कहा है, **"यह अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली (Monetary System) को नहीं समझते। अगर समझते तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह होने से पहले क्रान्ति हो जाएगी।"**

तो ऐसी क्या बात है, जिसे अगर देश के लोग समझ लें तो क्रान्ति होनी निश्चित है! इस बात को समझने के लिए हमें बैंकिंग प्रणाली के साथ यह भी समझना होगा की आखिरकार यह 'पैसा' है क्या?

3
एक रुपये का नोट और अन्य नोट

जैसा की ऊपर के चित्रों में आप देख रहे हैं, तीन तरह के रुपये हैं, एक रुपया चाँदी का है जो कि भारत सरकार ने जारी किया है, जिसकी कीमत एक तोला (10 ग्राम) चाँदी है। दूसरे चित्र में आप एक रुपये का नोट देखेंगे, यह भी भारत सरकार ने जारी किया है और इस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। तीसरी तस्वीर में एक रुपये का सिक्का है और यह भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

लेकिन 2 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक सभी नोट अलग तरह के मिलेंगे। इसमें पहला अन्तर यह है कि यह भारत सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार ने इसे गारंटी दी है। इन नोटों में से आप यहाँ एक 100 रुपये के नोट की तस्वीर देखो। जिस पर लिखा है - **"मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।"** और इस के नीचे भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह की बात आप 2 से 2,000 रुपये के सभी नोटों में देख सकते हैं, जो बात एक रुपये के नोट में नज़र नहीं आती है।

मतलब यह है कि यह 100 रुपया नहीं है सिर्फ 100 रुपये की रसीद है जिसे अगर आप भारतीय रिज़र्व बैंक को दें तो 1933 से पहले वह आपको 100 चाँदी के रुपये देता, परन्तु अब नहीं मिलेंगे। इसी बात को आगे विस्तृत रूप से समझाया जाएगा।

4
बैंकों का जन्म

पश्चिमी देशों में पहले लोग सुनारों के पास अपना सोना-चाँदी सुरक्षित रखते थे। बदले में वो रसीद देते थे। जब कोई सुनारों के पास 100 तोला चाँदी के सिक्के यानी 100 रुपया जमा करने जाता था तो बदले में वो उसे एक कागज़ की रसीद अपनी मोहर लगाकर देता था, जिस पर लिखा रहता था कि "मैं धारक को 100 तोला चाँदी देने का वचन अदा करता हूँ"।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज	Money Supply पैसे की मात्रा
100						

यह रसीद आज के नोट की तरह रहती थी, जिस रसीद को वह व्यक्ति अगर सुनार को वापस देता तो उसे 100 तोला चाँदी मिल जाती। धीरे-धीरे इस रसीद पर लोगों का विश्वास बन गया कि कोई भी व्यक्ति यह रसीद लेकर जारी करने वाले सुनार के पास लेकर जाएगा तो बदले में उसे उतनी चाँदी मिलेगी। इस प्रकार यही रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगी और बहुत कम लोग असली चाँदी सुनारों से माँगते थे।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100					

आम तौर पर उसे वापिस लेने के लिए एक समय में 10 प्रतिशत से भी कम लोग आते थे। इसे देखते हुए सुनारों ने 10 प्रतिशत अपने पास जमा रखकर बाकि सोना और चाँदी लोगों को ऋण के रूप में ब्याज पर देना शुरू किया। इस तरह सोना और चाँदी अब अन्य-अन्य लोगों के पास से घूमता हुआ वापस सुनारों के पास आने लगा। उसका भी 10 प्रतिशत रखकर बाकि फिर से ब्याज पर चढ़ाया जाने लगा और इस तरह से एक ही सोने को कई बार ब्याज पर दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को बैंकिंग की भाषा में अंश रिज़र्व बैंकिंग (Fraction Reserve Banking) कहा जाता है। इन लोगों को मनी चेंजर कहते थे।

सुनारों ने व्यवस्था बनाई कि जब कोई व्यक्ति रसीद के बदले सोना या चाँदी माँगने आए तो उसे वह लौटा दिया जाए और बाकी के सोना या चाँदी (जो आम तौर पर लगभग 90 प्रतिशत होता था और सुनारों के पास जमा रहता था) को उसके असली मालिक से बिना पूछे वे कर्ज के रूप में देकर ब्याज कमाते थे।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100	100	10	90	5.4	190

मान लो किसी शहर में कुल 100 तोला चाँदी है जो एक सुनार के पास जमा है। इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिज़र्व के रूप में रख लेता है और शेष 90 तोला को ऋण के रूप में ब्याज पर देता है। ब्याज की दर अगर 6 प्रतिशत वार्षिक भी हो तो 90 तोला चाँदी का वार्षिक ब्याज 5.4 तोला बनता है। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई कि देश में पैसे की मात्रा जो 100 थी अब वह 190 हो गई। एक तरह से 90 की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना कर दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यहीं नहीं रुकी। कर्जघ्पर 90 तोला चाँदी लेने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा। इस तरह वह चाँदी बाज़ार में घूमकर अन्ततः उसी सुनार के पास जमा हो जाएगी। जिसके बदले सुनार फिर से वायदे की एक रसीद काट कर दे देगा। उसका भी 10 प्रतिशत रखकर बाकी का पैसा कर्जध्के रूप में दे दिया जाएगा, जिस पर वह और ब्याज लेगा और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100	100	10	90	5.4	190
90	90	190	9	81	4.86	271

ऊपर की तस्वीर में आप देखेंगे की 90 तोला चाँदी में से 9 तोला रखकर 81 तोला कर्जष्के रूप में दी गई, जिस पर 4.86 तोला का ब्याज मिला और पैसे की मात्रा बढ़कर 271 हो गई।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100	100	10	90	5.4	190
90	90	190	9	81	4.86	271
81	81	271	8.1	72.9	4.37	343.9
72.9	72.9	343.9	7.3	65.6	3.93	409.5
65.6	65.6	409.5	6.6	59	3.54	468.5
59	59	468.5	5.9	53.1	3.18	521.6
इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि
इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि
इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि
इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि	इत्यादि
1000	1000	1000	100	900	54	1000

इसी तरह से यह प्रक्रिया बार-बार चलती रहने पर अन्त में असल रूप में 100 तोला चाँदी होते हुए भी 1,000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है। जिसके बदले 1,000 तोला की रसीद देश में फैल जाती है। जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर 1,000 हो जाती है, जबकि कुल 100 तोला चाँदी अभी भी रिज़र्व के रूप में सुनार के पास रखी है। (कृपया यह ध्यान रखें कि सुनार द्वारा जारी चाँदी की रसीद बाज़ार में प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही है।) 100 तोला चाँदी होते हुए भी सुनार ने 900 तोला चाँदी रहस्यमयी ढंग से कर्ज पर दे रखी है। जिस पर वह सालाना 54 तोला चाँदी ब्याज के रूप में वसूलता है। परन्तु असलियत में यह प्रक्रिया किसी और ढंग से घटित होती है, जिसे हमें किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं समझाया गया है। इसे आगे समझाने का प्रयत्न किया गया है।

5
आधुनिक पैसे की प्रक्रिया

1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिज़र्व द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया *Modern Money Mechanics* नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमें साफ लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वे ऐसा करते तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। वे ऋण (loan) देते समय उधारकर्ताओं के लेन-देन खातों में क्रेडिट के बदले में 'वचन नोट' स्वीकार करते हैं।

जिसका अर्थ यह है की जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो वे पहले से जमा पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते, बल्कि आपसे कहते हैं कि आप हमें यह वचन दो की आप जितना पैसा ऋण लेंगे उसे आप ब्याज समेत वापस लौटाओगे। आपके इस वायदे के बदले में वो एक रसीद काटकर देते हैं, जिसे आप पैसा मान लेते हो। सुनार भी ऐसा ही करते थे जिसे पहले समझाया गया है।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100		100			100

हमने पहले जो प्रक्रिया देखी उसमें सुनार 10 प्रतिशत रिज़र्व रखकर बाकी का सोना-चाँदी कर्ज पर देता था। पर असलियत में वह सारा का सारा सोना चाँदी रिज़र्व के रूप में रखता था। अभी पैसे की मात्रा 100 ही थी जिसे ऊपर की चित्र में दिखाया गया है।

आगे की प्रक्रिया में जब कोई सुनार के पास पैसे लेने जाता था तो सुनार उससे वचन लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार लिए गए पैसे को ब्याज सहित लौटाएगा। इस वायदे को अपनी सम्पति मानकर सुनार उतना पैसा नहीं होते हुए भी उसे उतना पैसा देने की बात करता था। चूँकि असल में उतनी चाँदी तो सुनार के पास थी ही नहीं, तो

वह कहता कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है वह मैंने अपने पास जमा कर लिया है। इसके बदले वह उस व्यक्ति को एक रसीद काटकर दे देता था जिसे लोगों ने पैसे (प्रतीकात्मक मुद्रा) के रूप में स्वीकार कर रखा था।

इस तरह सुनार द्वारा जारी की गई रसीदों पर लोगों का विश्वास होने के कारण उसके घर में एक तरह से पैसे बनाने की मशीन आ गई। जिसे वह अपनी मनमर्ज़ी से प्रयोग करता था। सुनार के पास जितना सोना-चाँदी रखा रहता था वह उससे दस गुना रसीद दे देता था (पैसा छाप लेता था)। जिसका दसवाँ हिस्सा तो सही मायने में उसे बनाने का अधिकार था, पर बाकी के नौ हिस्से वह अपनी मनमर्ज़ी से बनाकर कर्ज देकर ब्याज वसूलता था। ऊपर दिए गए चित्र में में आप इसे समझ सकते हैं।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100		100			100
		900		900		
900	900				54	1000

इस तरह सुनार असली पैसे (सुनार के पास जमा सोना-चाँदी; वास्तविक मुद्रा) से नौ गुना पैसा ऋण देता था। अगर उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगे, तो वह 6 प्रतिशत ना रहकर (9 x 0.06 x 100 = 54%) 54 प्रतिशत हो जाता था। 54 प्रतिशत सालाना ब्याज का अर्थ है दो साल में सारा सोना-चाँदी इनका हो जाना।

चूँकि सब लोग अपना सारा पैसा सुनारों के पास नहीं रखते थे इसलिए दो साल की जगह इस काम को होने में कई साल लगे। दुनिया का लगभग सारा सोना-चाँदी जब

इनका हो गया, तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोने-चाँदी के आधार पर ऐसे ही पैसा छापकर कर्ज पर देने का निर्णय किया गया। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंकों के पास जमा सोना-चाँदी नहीं मिलेगा। यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है की कोई भी देश अपने पास रखे हुए सोने-चाँदी के आधार पर पैसा बना सकता है। अब सुनारों ने कागज़ का नोट बनाने का अधिकार तो केन्द्रीय बैंक, जैसे - भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), फेडरल रिज़र्व बैंक वगैरह को दे दिया, परन्तु दुनिया के अधिकांश केन्द्रीय बैंक प्राइवेट हैं और इन्हीं लोगों की सम्पति हैं। जो केन्द्रीय बैंक सरकारी हैं, जैसे - भारतीय रिज़र्व बैंक, इन्हीं लोगों की व्यवस्था के अन्तर्गत हैं और सरकार का नियंत्रण केन्द्रीय बैंको पर न्यूनतम है। इसी कारण आप भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट पर पाएँगे कि केन्द्रीय सरकार इस पर गारंटी दे रही है ताकि लोगों का विश्वास इस कागज़ पर बना रहे।

अब सुनारों ने हर जगह अपने बैंक बना लिए और जैसे वे पहले सोना-चाँदी रखकर कागजध्की रसीद काटते थे, अब केन्द्रीय बैंक द्वारा बनाए गए पैसे को रखकर दस गुना पैसा कर्ज के रूप में दे देते हैं। जो सिर्फ लोगों के बैंक खाते में लिखे रहते हैं, जबकि असलियत में बैंकों के पास होते ही नहीं हैं। जब तक सोना-चाँदी था, तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे, लेकिन अब ये लोग कागजध्के नोट रखकर अनन्त पैसा बना सकते हैं। **अंश रिज़र्व बैंकिंग की इस प्रक्रिया से दुनिया का 90-95 प्रतिशत पैसा केन्द्रीय बैंक नहीं बल्कि व्यावसायिक बैंक बनाते हैं।** एक तरह से पैसे बनाने का असली अधिकार किसी केन्द्रीय बैंक जैसे - भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकार के पास ना होकर किसी नुक्कड़ चौराहों पर स्थापित व्यावसायिक बैंको के पास हैं, जैसे - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, इत्यादि और इनकी लगाम विदेशी ताकतों के पास है।

आज के समय जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा कराने जाता है तो बैंक आपके खाते में पैसे लिखकर आपको एक पासबुक या कागजध्के नोट दे देती है, जैसा कि नीचे की चित्र में दर्शाया गया है।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100		100			100
		900		900		
900	900				54	1000

जब किसी को कर्ज की जरूरत पड़ती है तो बैंक सुनारों की तरह आपसे एक वायदा लिखवा लेते हैं कि आपको ब्याज सहित कर्ज वापस लौटना पड़ेगा। जिसके बदले वो आपको कर्ज देने की बात करते हैं। पर असली पैसा ना होने की वजह से वो सिर्फ आपके खातों में लिख देते हैं जिस पर वे आपसे ब्याज वसूलते हैं।

अब अगर किसी को एक लाख रुपये कर्ज के रूप में चाहिए तो बैंक दे देते हैं और आपके खातों में लिख देते हैं, लिखे गए पैसों का 10 प्रतिशत यानि 10,000 रुपये ही रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस व्यवस्था को आप नीचे दी गई तस्वीर से समझ सकते हैं।

Deposits जमा राशि	Receipt रसीद	Money Supply पैसे की मात्रा	Reserve रिज़र्व	Loan कर्ज	Interest ब्याज (6%)	Money Supply पैसे की मात्रा
100	100		100			100
		900		900		
900	900				54	1000
		1,00,000		1,00,000		
1,00,000	1,00,000				6000	1,01,000
			10,000		-600	

इस पूरी प्रक्रिया में पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो महँगाई का मुख्य कारण है। इसे आगे विस्तार से बताया गया है।

केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितना पैसा बनाकर बैंक कर्ज के रूप में देंगे उसका 10 प्रतिशत बैंको को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता था। जो या तो लोगों के द्वारा जमा किए गए पैसे से ही हो जाता है और अगर नहीं होता तो वे केन्द्रीय बैंक से बहुत सस्ते ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं। **एक तरह से बैंक वालों के घर में पैसे का पेड़ है जिससे पैसे तोड़कर कितने भी पैसे कर्ज के रूप में दे सकते हैं।**

6

पैसा बनता कैसे है?

जब भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो जनता पर टैक्स लगाती है और आवश्यकता पूरी ना होने पर भारत सरकार अपना खुद का पैसा ना बनाकर कर्ज पर पैसे लेती है।
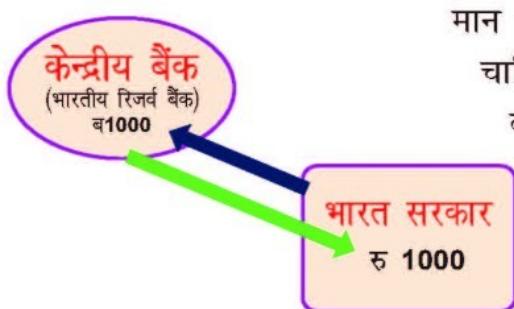
मान लो कि भारत सरकार को 1,000 रूपए चाहिए तो वह कागज़ पर बैंक को यह वायदा करती है कि ब्याज समेत पैसा लौटा देगी। इस वायदे को सरकारी प्रतिभूति (बांड) कहते हैं। जिसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास लेकर जाता है और बदले में भारतीय रिज़र्व बैंक 1,000 रुपये का नोट छापकर भारत सरकार को दे देता है।

अब मान लिया जाए की भारत सरकार ईमानदार लोगों द्वारा संचालित है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, तो वह सारे रुपये जनकल्याण की योजना में खर्च कर देती है। पैसा जनता के पास पहुँचता है और जनता इस एक हज़ार रुपये को व्यावसायिक बैंकों, जैसे - आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि में जमा कर देती है और बदले में बैंक उनके खाते में पैसा लिख देता है।
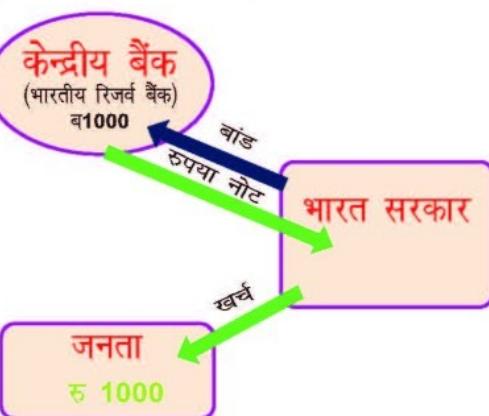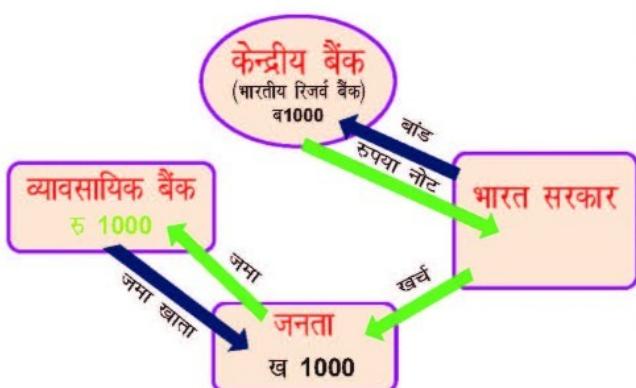
अब इस एक हज़ार के नोट को रखकर व्यावसायिक बैंक 9 गुणा पैसा कर्ज के रूप में दे सकता है। भारत में तो यह 24 गुणा तक है। पैसे की मात्रा बढ़ने से आई महँगाई को रोकने का हवाला देकर अब केन्द्रीय बैंक इस एक हज़ार रुपये के बांड को व्यावसायिक बैंक को एक हज़ार रुपये में बेच देता है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है।

केन्द्रीय बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक)
ब1000
ओपन मार्केट ऑपरेशन
बांड
रुपया नोट
व्यावसायिक बैंक
ब1000
भारत सरकार
जमा
खर्च
जमा खाता
जनता
ख 1000
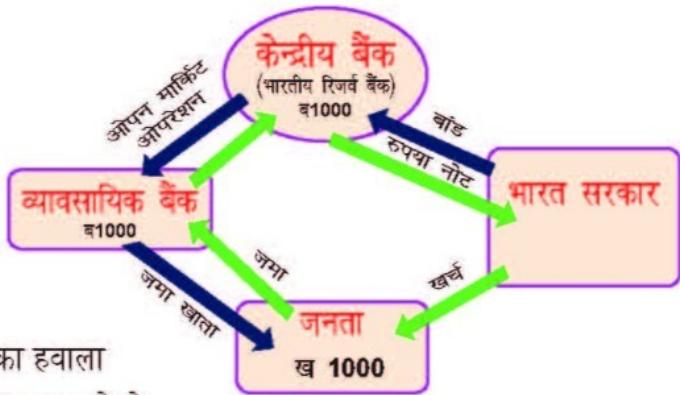
अब आप देख पा रहे हैं कि केन्द्रीय बैंक द्वारा बनाया गया उसका 1,000 रुपये का नोट उसके पास वापस आ गया है, इस तरह केन्द्रीय बैंक पैसे ना बनाकर सिर्फ एक बिचौलिए का काम कर रहा है और जिसके बिना तस्वीर कुछ ऐसी होगी।
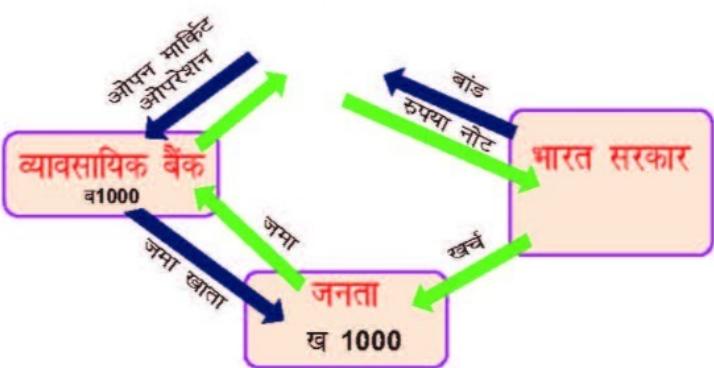
लाइनों को सीधा कर दे तो साफ दिखाई देता है की जब भी भारत सरकार को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो वह केन्द्रीय बैंक के माध्यम से व्यावसायिक बैंक को कर्जका बांड देती है और व्यावसायिक बैंको के पास कोई पैसा ना होते हुए भी वो उतना पैसा भारत सरकार के खाते में लिख देते हैं। खर्च करने पर वह पैसा भारत सरकार के खाते से अब जनता के खाते में लिखा रहता है, इसे आप आगे की तस्वीर में साफ देख सकते हैं।
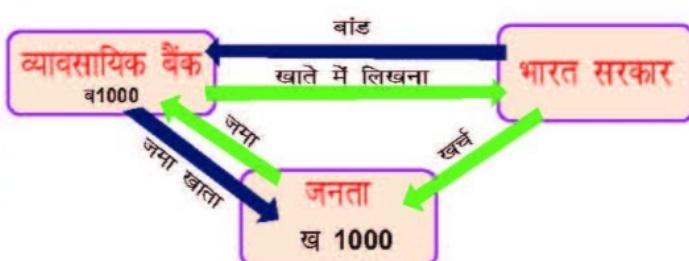
केन्द्रीय बैंकों का काम सिर्फ खातों में लिखे गए पैसों के लिए रिज़र्व रखने के लिए बैंकों को आवश्यक पैसों की आपूर्ति करना होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसे बैंक कर्ज के रूप में ले लेता है, इसे हम पहले भी समझ चुके हैं।
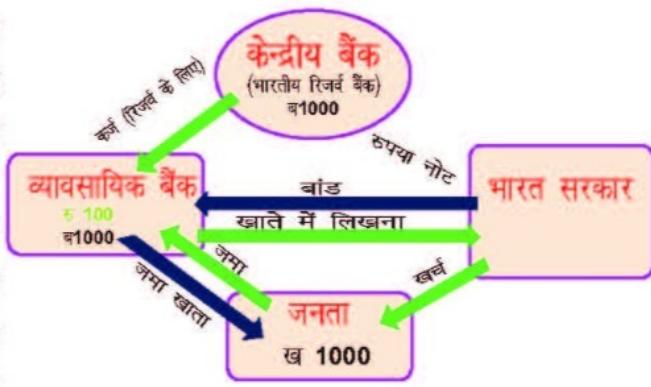
फेडरल रिज़र्व बोर्ड के अध्यक्ष मेरिनर ऐकिलिस 1935 में इस प्रक्रिया के बारे में लिखते हैं - "सरकारी बांड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए 1 अरब करोड़ डॉलर के बांड खरीदता है तो वो सरकारी खाते में 1 अरब करोड़ डॉलर लिख देता है। इस तरह से वे सिर्फ खाते में लिखकर 1 अरब डॉलर पैदा कर देते हैं।"

इस प्रक्रिया को और आसानी से अगली तस्वीर से समझा जा सकता है।
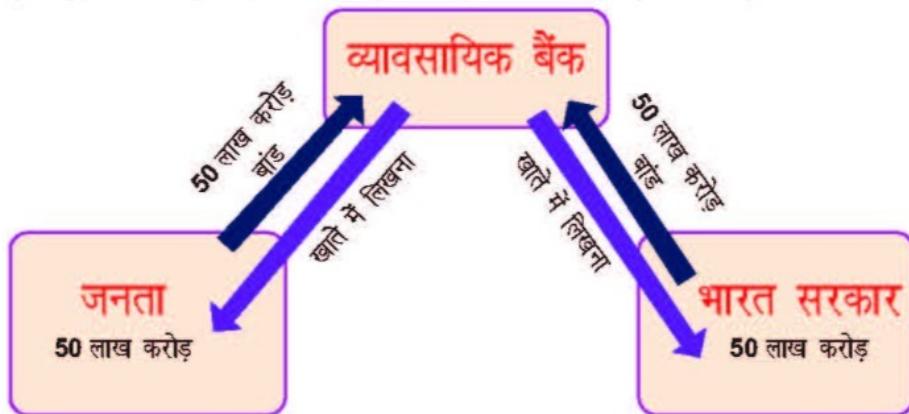
इसमें जब भी भारत सरकार या देश की जनता को कर्जध्लेने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे ब्याज समेत पैसा लौटाने का वायदा लिखकर व्यावसायिक बैंक के पास जाते हैं; जिसके बदले व्यावसायिक बैंक उतनी ही रकम आपके खाते में चढ़ा देता है। जिस पर सालाना लाखों-करोड़ों रुपया ब्याज माँगते हैं। खाते में लिखे गए पैसे का 10 प्रतिशत रिज़र्व के रूप में होना चाहिए, जिसे वे भारतीय रिजर्घ बैंक से कर्ज पर लेते हैं। इस तस्वीर में आप इसे समझ सकते हैं।
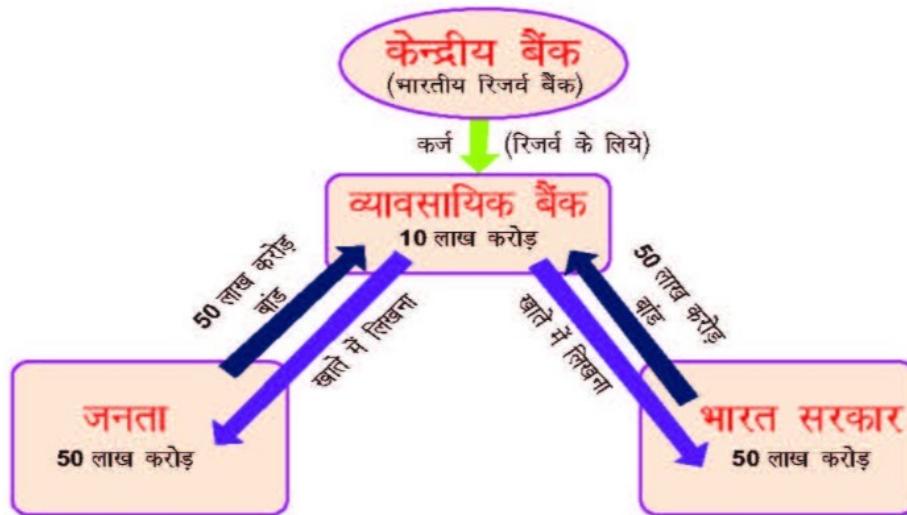
इस तरह से देश के 95 प्रतिशत पैसे बनाने का काम व्यावसायिक बैंकों का है। जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है। भारतीय रिज़र्व बैंक मात्र 5 प्रतिशत पैसे ही बनाता है, जो कागज़ के नोट के रूप में दिखाई पड़ते हैं।
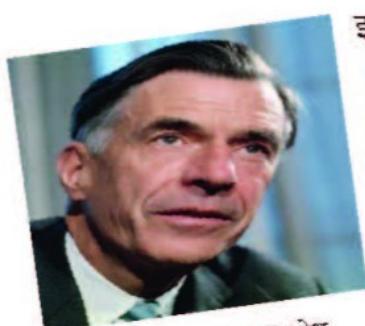
इस विषय पर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ कहते हैं, **"बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है।"** दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है।

जॉन केनेथ गालब्रेथ

रॉबर्ट बी. एंडरसन, अमेरिका के वित्त सचिव (1959), **"जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से नहीं लेकर देता। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने नया बनाकर दिया होता है।"**

7
क्रेडिट कार्ड स्कीम

क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करने पर कार्ड स्वैप करने के बाद आप एक परची पर अपने हस्ताक्षर करके दुकानदार को देते हैं। परची पर आपके हस्ताक्षर करते ही वह पैसा बन जाती है, जिसे व्यापारी अपने मर्चेंट अकाउंट में जमा कर देता है। यह परची क्रेडिट कार्ड कम्पनी को भेज दी जाती है जिसके बण्डल बनाकर वह बैंकों को भेज देती है। बैंक आपको एक स्टेटमैंट भेज देता है जिसका आप भुगतान कर देते हो। पूरी प्रक्रिया में कहीं भी बैंक ने आपको अपनी जेब से या अपने जमा खातों में से कोई पैसा दिया? बल्कि वह आपकी चार्ज स्लिप पर किए वायदे को अपनी सम्पत्ति दिखाकर क्रेडिट में बदल देता है।

आपका वायदा ही पैसा है। अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दो, तो आपकी सम्पत्ति घट जाएगी; पर उधार देने पर बैंकों की सम्पत्ति बढ़ जाती है। आपका वायदा उनकी सम्पत्ति बन जाता है जिसके बदले वे आपके खातों में उतने अंक लिख देते हैं। जिसे आप पैसा मानते है।

8

नए पैसे को मूल्य कौन देता है?

मान लो कोई चीज 100 रुपये की आती है और अब बैंकों ने नया पैसा बनाकर कर्ज दे दिया, जिससे देश के पैसे की मात्रा 10 प्रतिशत बढ़ गई। अब वह चीज़ 110 की आएगी। बैंक हमारी ही जेब से मूल्य चुराकर कर्ज का पैसा देते है। इस चोरी को महँगाई कहते हैं। हर साल हमारे पैसे को हमें ही कर्ज पर देकर बैंक ब्याज और महँगाई से लाखों करोड रुपये लूट लेते हैं।

महँगाई इसी बैंकिंग प्रणाली का नतीजा है। कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए या किसी भी दल की सरकार बन जाए, बिना इस व्यवस्था को बदले महँगाई को काबू में नहीं लाया जा सकता।

9
कोर्ट में चुनौती

अमेरिका में 1967 में डेली नामक व्यक्ति ने घर बनाने के लिए 14,000 डॉलर का ऋण (होम लोन) यह कहकर लौटाने से मना कर दिया कि बैंक ने उसे कोई असली पैसे दिए ही नहीं। पहले तो सबको यह दलील एक बकवास लग रही थी। पर जब बैंक के मालिक जे.पी. मोरगन ने माना कि "बैंक तो लोन के पैसे हवा में से बनाता है" तो न्यायधीश मार्टिन महोने चौंककर बोले, "यह मामला मुझे धोखाधड़ी (fraud) लग रहा है" और फैसला डैली के हक में सुना दिया।

पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह एक खतरा होता अगर सभी अपना कर्जा देने से मना कर देते। न्यायधीश मार्टिन महोने ने बाद में जब इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की तो 6 महीने के अन्दर रहस्यमयी ढंग से ज़हर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।

10
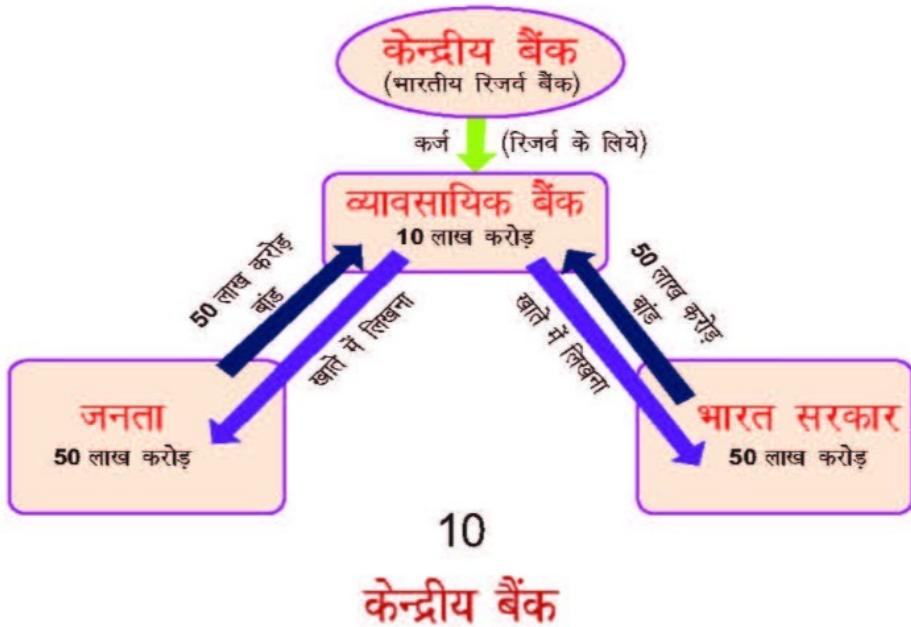
केन्द्रीय बैंक

केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण काम देश में पैसे की मात्रा (money supply) नियंत्रित करने का है जिसे वह ओपन मार्केट औपरेशंस के अलावा दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के द्वारा करता है।

- ब्याज दरें या रिजर्ष रेशो घटाकर
- ब्याज दरें या रिजर्ष रेशो बढ़ाकर

जब केन्द्रीय बैंक ब्याज दरें या रिजर्ष रेशो घटा देता है तो सस्ते ब्याज होने से और बैंको के पास ज़्यादा पैसा होने के कारण देश में लोग ज़्यादा कर्ज लेते हैं। इस वजह से पैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ज़्यादा पैसा होने से महँगाई का दौर आता है। बैंक लोगों से, ब्याज से और सस्ते पैसे से निवेश करके खूब कमाते हैं।

जब पैसे की मात्रा बढ़ जाती है तो महँगाई कम करने का टॉनिक देकर ब्याज दरें या रिजर्ष रेशो बढ़ा दी जाती है, जिससे एकाएक देश में पैसे का अकाल पड़ जाता है। कम पैसा (शॉर्ट मनी) होने से मन्दी का दौर आता है और जिसमें ये लोगों के माल को कौड़ियों के भाव खरीद कर लूटते हैं, जिसे आगे समझाया गया है।

11
मन्दी क्या है?

जब बैंक पैसे की कमी कर देते हैं तो बाज़ार में वस्तुओं और सेवाओं की माँग घट जाती है। वस्तुएँ भी होती हैं और लोगों को उनकी ज़रूरत भी होती है, पर पैसे न होने से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। बिक्री ना होने से हर किसी का काम-धन्धा ठप पड़ जाता है। इससे लाखों लोगों की नौकरी चली जाती हैं। पढ़े-लिखे होने पर भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता। इसमें वे या तो अपने आप को या भगवान को दोषी ठहराने लगते हैं।

करोड़ों मज़दूरों को भी काम नहीं मिलता, क्योंकि धन्धे में मन्दी की वजह से काम देने वालों के पास भी पैसा कम हो जाता है। पैसों के अभाव में देश में खाना होते हुए भी रोटी तक नसीब नहीं होती। करोड़ों लोग रोज़ध्भूखे सोते हैं और इससे होने वाले कुपोषण से और बीमारियों से हर रोज़ध्हजारों बच्चे मर जाते हैं। खाने की माँग में कमी होने से किसान की फसलों, फलों और सब्जियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। एक तरह से पूरी व्यवस्था का चक्का जाम हो जाता है। मजबूरी में किसान अपनी ज़मीन और उद्योगपति अपना उद्योग सस्ते में बेचने को, 50 हजार की आशा रखने वाला पढ़ा-लिखा युवा 5,000 में, मज़दूर सस्ते से सस्ते मेहनताने पर काम करने को और ओडीसा के कालाहाण्डी में एक माँ 20 रुपये में अपने छोटे से बच्चे को बेचने पर मज़बूर होती है। कुल मिलाकर हर कोई बर्बाद हो जाता है।

रॉबर्ट एच. हैम्फिल, फेडरल रिज़र्व बैंक के प्रबन्धक (1934) - **"हम वाणिज्यिक बैंकों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। हममें से किसी न किसी को हर हाल में नकद या क्रेडिट में डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। अगर बैंक पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते हैं तो हम समृद्ध हो जाते हैं; यदि नहीं तो हम भूखे मरते हैं।"**

फेडरल रिज़र्व बोर्ड के अध्यक्ष, मैरिनर एक्लिस (1941) - **"अगर हमारी पैसे की व्यवस्था में कर्जध्नहीं होगा तो देश में एक भी पैसा नहीं होगा।" क्योंकि पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है।**

12
ब्याज कहाँ से आए?
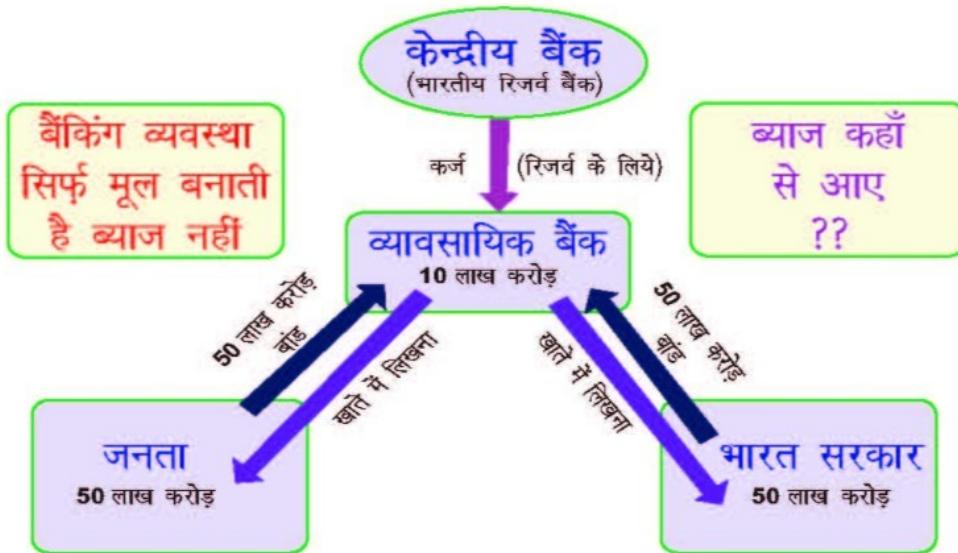
पूरी बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ मूल बनाती है ब्याज नहीं। तो, सवाल उठता है कि आखिरकार ब्याज कहाँ से आए? इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं :

मान लो किसी बैंक ने 100 लोगों को 100-100 रुपये कर्जघदिया और मान लो कि सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपये कर्ज लिया। इस तरह कुल कर्ज हुआ 20,000 रुपये; इस पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया गया। अतः एक साल बाद हमें बैंक को 22,000 रुपये लौटाने होंगे। लेकिन बैंक ने कुल 20,000 रुपये ही जारी किए हैं, जिसकी वजह से चलन में कुल 20,000 रुपये ही हैं। इस स्थिति में ब्याज के 2,000 रुपये लौटाना असम्भव है।

यह प्रक्रिया कुर्सी के उस खेल की तरह है जिसमें कुर्सी कम होती हैं और खेलने वाले व्यक्ति ज़्यादा। ताली बजने पर सब लोगों को कुर्सी पर बैठना है, परन्तु कुर्सी कम होने के कारण सब लोग उन पर नहीं बैठ पाएँगे, किसी एक को हमेशा खड़े ही रहना है। यह खेल निरन्तर चलता रहता है।

कहते हैं प्रेम, युद्ध और कॉम्पीटिशन में हर चीज़ जायज़ है। यह व्यवस्था कॉम्पीटिशन

पैदा करती है। इसलिए पूरा समाज पागल होकर, अपना धर्म और कर्तव्य भूलकर एक ही चीज़ में लगा है - अधिक से अधिक धन कमाना! हर कोई कहता है कि कलयुग आ गया है, लोग लालची हो गए हैं, लोग बुरे हो गए हैं, अब सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोग हार मान लेते हैं, परन्तु कुछ समाजसेवी, सन्त-महात्मा यह समझाने में लगे हुए हैं कि संग्रह मत करो; जो इस व्यवस्था में कभी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग इस अभियान में लगे हैं कि अगर पूँजीपति अपना सारा धन गरीबों में बाँट दें, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। किन्तु इस व्यवस्था में यह भी असम्भव है। सब लोग अपने वर्ग के शोषण का कारण किसी दूसरे वर्ग को ठहरा देते हैं। व्यापारी, मज़दूर, किसान एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं कि ये हमें लूट रहे हैं; पर सच्चाई यह है कि इस व्यवस्था के चक्रव्यूह में हर कोई लुट रहा है और लूटने वाला कोई और ही है, जिसे सत्संग और प्रवचनों द्वारा सही नहीं किया जा सकता।

बर्नार्ड लिएटर

13
बेरोज़गारी, भुखमरी और लालच क्यों?

यूरो सिस्टम के निर्माण में सहायक रहे बर्नार्ड लिएटर लिखते हैं **"लालच और प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं हैं, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है; जो हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे पैसे (प्रतीकात्मक मुद्रा) का एक सीधा परिणाम है। सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केन्द्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करे और कमी को बनाए रखे। इसका सीधा परिणाम यह है कि हमें जीवित रहने के लिए एक-दूसरे के साथ लड़ना पडता है।"**

इस व्यवस्था में जो ईमानदार लोग दूसरों को लूट या मार नहीं सकते, उनके पास इस व्यवस्था से समझौता करना या फिर आत्महत्या करने का ही विकल्प बचता है। इस व्यवस्था में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है।

14
आत्महत्याएँ

बचपन में भविष्य सुरक्षित करने के लिए पढ़ाई के दबाव में, जवानी में नौकरी ना मिलने पर युवक-युवतियों की शादी होने में भी दिक्कतें आती हैं, इस निराशा में हजारों नौजवान आत्महत्या करते हैं; इस व्यवस्था में सबके लिए जगह नहीं है। बैंकों द्वारा पैदा किए गए ये कृत्रिम अभाव, गरीबी और स्पर्धा लोगों को चोरी, लूट, हत्या, धोखाधड़ी और आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। हर साल भारत में लगभग 15,000 किसान आत्महत्या करते हैं और पूरे विश्व में हर साल होने वाली कुल 8 लाख आत्महत्याओं में से 1,35,000 (17 प्रतिशत) भारत में होती हैं।

15

आत्महत्या या हत्या?

एक समुदाय में मांस खाने के लिए जानवरों की हत्या करना मना था। मांस खाने के लिए कुछ लोग एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलता हुआ तेल डालकर उस पर एक पतला सा फट्टा रख देते थे। बकरी को उस फट्टे पर चढ़ाकर दोनों ओर से रास्ता बन्द कर देते थे। कुछ देर बाद बकरी तेल में कूदकर आत्महत्या कर लेती थी और वे उसे खा लेते थे।

यह आत्महत्या है या हत्या?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में हम सबको जीने का अधिकार मिला है। यह व्यवस्था मौलिक मानवीय अधिकार का उल्लंघन है। किसानों की आत्महत्या के दोषी बैंक हैं, जिन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
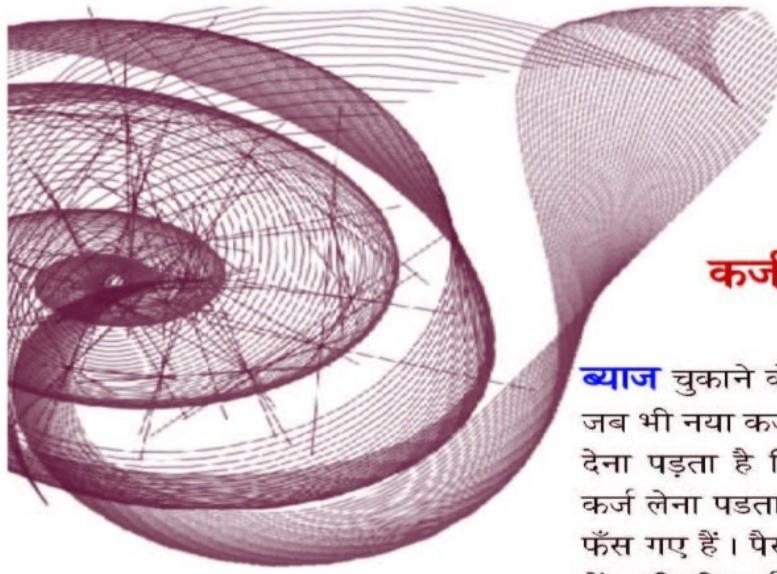
16

कर्ज का जाल

ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है और जब भी नया कर्ज लेते हैं, तो उस पर भी और ब्याज देना पड़ता है जिसे चुकाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पडता है। इस तरह हम कर्ज के जाल में फँस गए हैं। पैसा ही कर्ज है इसलिए इस व्यवस्था में कभी भी कर्ज मुक्त होना असम्भव है।

इस व्यवस्था में अगर सारा पैसा वापस भी कर दिया जाए तो भी हम पर कर्ज शेष रहेगा। क्योंकि देश में जितना पैसा है उससे अधिक कर्ज है, जो ब्याज की व्यवस्था के कारण है।

अगली सरकार को लौटाना होगा 10 लाख करोड़

कर्ज के भंवर में डूबा देश

कर्ज एक नजर

33,82000 करोड़ कुल कर्ज था

03,40000 करोड़ विदेशी कर्ज

30,42000 करोड़ भारतीय कर्ज

चुकाना होगा अगली सरकार को, क्या कांग्रेस यह मान बैठी है कि अगली सरकार उसकी नही बनने वाली

पिछले दो साल में प्रणव मुखर्जी ने ही बढ़ाया दो लाख करोड़ का कर्ज

शेष पृष्ठ 7 पर
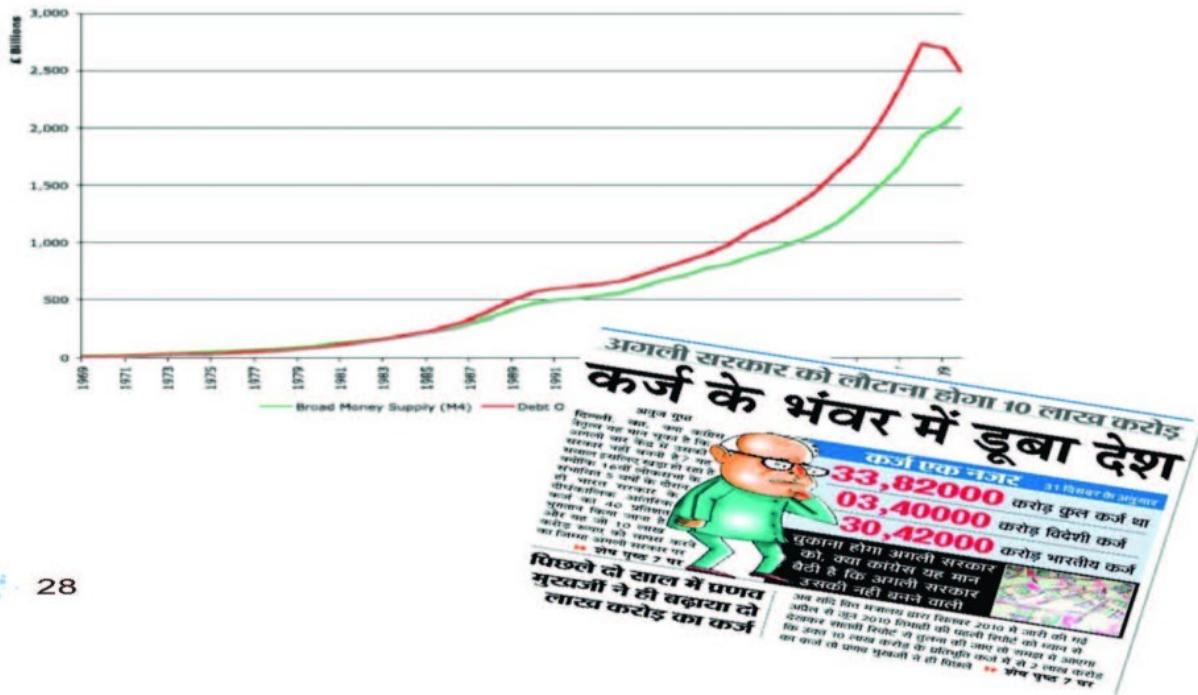
17
बन्धुआ मजदूरी

अगर 5 सिक्के (English pennies) 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिए जाएँ तो 1,850 सालों में 32,36,66,48,157 पृथ्वी जितने बड़े सोने से भरे गोले ब्याज के रुप में देने पड़ेंगे।
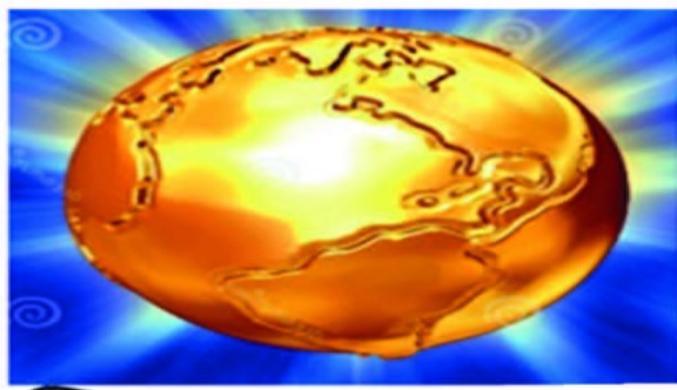
पूरा जीवन हम उस पैसे का ब्याज भरने के लिए काम करते रहते हैं जो बैंकों का है ही नहीं और कभी चुकाया नहीं जा सकता। इस प्रकार यह एक तरह की बन्धुआ मजदूरी है जो संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन और हमारे मूलभूत अधिकार का हनन है।

18

बजट 2015-2016

सरकार ने टैक्स के रूप में 14,49,490 करोड़ रुपये एकत्रित किए जिसमें से 5,23,958 करोड़ रुपये राज्यों को उनके हिस्से के रूप में दिए। 2,21,733 करोड़ रुपये की सरकार की आमदनी जोड़ने से कुल आय 11,41,575 करोड़ रुपये हो जाती है। इस आय में से सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण इत्यादि) और आर्थिक सेवाओं (कृषि उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रोद्योगिकी इत्यादि) जैसे देश के जनकल्याण के कार्यों में मात्र 58,127 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि 6,81,719 करोड़ रुपया बैंको को सौंप दिए।

राजस्व प्राप्तियां	REVENUE RECEIPTS	
कर राजस्व	1. Tax Revenue	
सकल कर-राजस्व	Gross Tax Revenue	1449490
निगम कर	Corporation Tax	470628
आय कर	Taxes on Income	327367
सीमा शुल्क	Customs	208336
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	229808
सेवा कर	Service Tax	209774
घटाइए-राज्यों का हिस्सा	Less - State's share	523958
निवल कर राजस्व	Centre's Net Tax Revenue	919842
कर - भिन्न राजस्व	2. Non-Tax Revenue	
कुल कर - भिन्न राजस्व	Total Non-Tax Revenue	221733
कुल राजस्व प्राप्तियां	Total Revenue Receipts	1141575
3. पूंजी प्राप्तियां	3. Capital Receipts	
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां	A. Non-debt Receipts	80253
ख. ऋण प्राप्तियां	B. Debt Receipts*	543608
जोड़-पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख)	Total Capital Receipts (A+B)	623861
4. नकदी का कम आहरण	4. DRAW-DOWN OF CASH BALANCE	12041
कुल प्राप्तियां (1+2+3+4)	Total Receipts (1+2+3+4)	1777477
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (3ख+4)	Financing of Fiscal Deficit (3B+4)	555649

राजस्व व्यय		
ब्याज संदाय और पूर्वदत्त लाभांश	Interest Payments and Prepayment Premium	456145
रक्षा सेवाएं	Defence Services	152139
सब्सिडी	Subsidies	243811
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	Grants to State and U.T. Governments	108552
पेंशन	Pensions	88521
पुलिस	Police	51791
सामाजिक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण, आदि)	Social Services (Education, Health, Broadcasting etc.)	29143
आर्थिक सेवाएं (कृषि, उद्योग विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि)	Economic Services (Agriculture, Industry, Power, Transport, Communications, Science & Technology, etc.)	28984
कुल व्यय*	TOTAL EXPENDITURE*	1777477
ऋण शोधन*	DEBT SERVICING	
1. ऋण की वापसी-अदायगी**	1. Repayment of debt**	225574
2. कुल ब्याज अदायगियां	2. Total Interest Payments	456145
3. कुल ऋण शोधन (1+2)	3. Total Debt Servicing (1+2)	681719
4. राजस्व प्राप्तियां	4. Revenue Receipts	1141575
5. 3 से 4 तक का प्रतिशत	5. Percentage of 3 to 4	59.71%

19

सरकार को टैक्स देना बेवकूफी है

वर्ष 2015-16 के बजट में 11,41,575 करोड़ की आय में से भारत सरकार ने 4,56,145 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) ब्याज चुकाया है और 2,25,574 करोड़ रुपये (20 प्रतिशत) कर्ज चुकाया। अगर सरकार अपने पैसे खुद बनाती तो एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। राज्य सरकारों का भी इतना ही पैसा कर्ज का जाता है। टैक्स का 60 प्रतिशत सरकार बैंकों को क्यों सौंप देती है? हम डीजल, पैट्रोल, वैट, आयकर से लेकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से हज़ारों जगह लाखों रुपया टैक्स भरते हैं। क्यों? क्या हम बेवकूफ हैं? गधे हैं?

20

हर साल 25 लाख करोड़ की लूट

भारत सरकार से बैंको द्वारा लूट = 4,56,145 करोड़ रुपये

राज्य सरकारों से लूट (लगभग) = 3 लाख करोड़ रुपये

जनता से ब्याज की लूट (लगभग) = 5 लाख करोड़ रुपये

डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट (लगभग) = 12.5 लाख करोड़ रुपये

धीरे-धीरे हमारी सारी सम्पत्ति का अधिकांश भाग लूट लिया गया है। 100 रुपये का मतलब था 100 तोला = 1 किलो चाँदी, पर आज हमारे पास 100 / 40,000 x 100 = 0.25 प्रतिशत ही बचा है। 99.75 प्रतिशत धन लुट गया।

देश में अगर कुल 20 करोड़ परिवारों में यह पैसा बाँट दिया जाए तो प्रत्येक परिवार को सवा लाख रुपये सालाना मिलेगा। इसलिए अगर बैंकों का बहिष्कार करके हर कोई अपना बैंक खाता बन्द कर दें तो प्रत्येक परिवार को घर बैठे सवा लाख रुपये सालाना मिल सकता है।

नोट - डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट की प्रक्रिया का विश्लेषण अगली पुस्तक में होगा।

21
विश्व नियंत्रण का इतिहास

विलियम तृत्तीय और राजकुमारी मैरी

मनी चेंजर्स की मदद से आगे बढ़कर विलियम तृत्तीय 1677 में राजकुमारी मैरी से विवाह करके 1689 में इंग्लैंड का राजा बन गया। कुछ ही दिनों बाद फ्रांस से युद्ध हुआ और उसने मनी चेंजर्स से 1.2 मिलियन (12 लाख) पाउंड उधार माँगे। उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ सिर्फ ब्याज वापस देना था मूल नहीं:

मनी चेंजर्स

(1) मनी चेंजर्स को इंग्लैंड़ के पैसे छापने के लिए एक केन्द्रीय बैंक 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' की स्थापना की अनुमति।

(2) सरकार खुद पैसे नहीं छापेगी और बैंक सरकार को भी 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देगा, जिसे चुकाने की गारंटी के लिए सरकार लोगों पर टैक्स लगाएगी। सरकार के इस ऋण चुकाने के वायदे को बांड कहा जाता है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड को सभी केन्द्रीय बैंकों की "माँ" कहा गया है जिसकी स्थापना 1694 में हुई।

22
बैंकिंग किंग रोथशिल्ड परिवार की कहानी

1694 में 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' की स्थापना कुछ और लोगों ने की परन्तु बाद में रोथशिल्ड परिवार का उस पर नियंत्रण हो गया। जर्मनी में 1744 में एमशेल रोथशिल्ड का जन्म हुआ जिसे बैंकिंग किंग भी कहा जाता है। उसके 5 बेटे जन्मे और उसने पाँचों को अलग-अलग देशों में आर्थिक साम्राज्य को खड़ा करने के लिए भेजा। एमशेल ने 1 मई 1776 को कुछ लोगों के साथ मिलकर इल्यूमिलिटी (जागृत या प्रबुद्ध) नामक एक गुप्त संस्था बनाई। इन लोगों को लगता था कि दुनिया के सभी व्यक्ति भेड़-बकरी की तरह हैं और ईश्वर ने इन्हें सब पर शासन करने के लिए भेजा है।
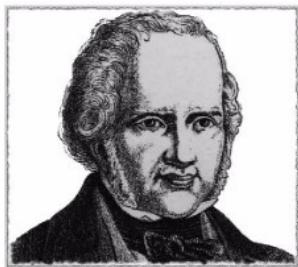
एमशेल रोथशिल्ड

उसका तीसरा बेटा नैथन रोथशिल्ड (1777-1836) बहुत शातिर था जिसे उसने इंग्लैंड में भेज दिया था। सन् 1815 में जब नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ तब उसके पास 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' के कुछ ही शेयर थे। अपने गुप्तचरों से उसे एक दिन पहले सूचना मिल गई थी कि नेपोलियन हार गया है। उसका दिमाग चला और उसने शेयर बाजार में अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया है। सबको यकीन दिलाने के लिए नैथन ने अपने आपको निराश दिखाते हुए अपने 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' के शेयर बेचने शुरू कर दिए। अगर सच में इंग्लैंड हार जाता तो 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' के शेयर की कीमत कुछ भी नहीं रह जाती। इस भय और अविश्वास के माहौल में फैली अफवाह से लोगों को उसकी बात पर यकीन हो गया और देखते ही देखते 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' के सभी शेयरधारकों ने अपने सभी शेयर बेचने शुरू कर दिए। इससे करोड़ों अरबों के शेयर कौडियों के भाव में आ गए, जिसे नैथन ने गुपचुप तरीके से अपने लोगों द्वारा खरीदवा लिया।

इस तरह एक अफवाह से, बिना कोई खास कीमत चुकाए वह एक दिन में ही 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' का मालिक बन गया। जब लोगों को पता लगा कि दरअसल नेपोलियन हार गया था, तो उनके पास सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।

नैथन रोथशिल्ड कहता है, **"अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है।"**

नैथन रोथशिल्ड

1820 में अपने ऊपर गर्व करते हुए रोथशिल्ड कहता है, "मुझे परवाह नहीं है कि किस कठपुतली को उस इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के 'पैसे की मात्रा' (money supply) को जो आदमी नियंत्रित करता है, ब्रिटिश साम्राज्य को भी नियंत्रित करता है और मैं ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को नियंत्रित करता हूँ।"

इस तरह से पूरी दुनिया से हर वर्ष करोड़ों-करोड़ रुपए लूटकर जुटाई गई इस एक बैंकिंग परिवार की सम्पति का आकलन 500 ट्रिलियन डॉलर लगाया गया है। अगर इस रकम का अन्दाजा लगाना हो कि यह कितनी है, तो समझ लीजिए की पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोग मिलकर एक वर्ष में सिर्फ 75 ट्रिलियन डॉलर की सम्पति पैदा करते हैं। इसे अगर रुपए में बदल दिया जाए तो यह सम्पति 30,00,00,00,00,00,00,000 रुपए की बनती है। जिसमें से अगर हर सैकंड खाते-पीते, सोते-जागते 1 करोड़ खर्च करें... तो इसे खर्च करने में 95 साल लगेंगे।

एमशेल रोथशिल्ड ने अपनी वसीयत में यह साफ-साफ लिखा था कि परिवार की सम्पति बँटेगी नहीं और परिवार का मुखिया ही इसे नियंत्रित करेगा। इस समय ऐवलिन रोथशिल्ड इस परिवार का मुखिया है। एक तरह से दुनिया का असली शासक रोथशिल्ड परिवार है।

ऐवलिन रोथशिल्ड

23

अमेरिका की कहानी

1729 में बेंजामिन फ्रेंकलिन एक नौजवान था और अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। उस समय उसने अपने अखबार में एक लेख लिखा कि अमेरिका के लोगों को बिना सोना-चाँदी के आधार पर कागज़ के कर्ज मुक्त नोट बना लेने चाहिए। लोगों को यह लेख बहुत पसन्द आया और सच में अमेरिका में कागज़ के पैसे बनने लगे। पैसे की मात्रा बढ़ने से अमेरिका में एकाएक समृद्धि आ गई। इस बात से इंग्लैंड में बैठे बैंकरों को अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई दिया और उन्होंने 1751 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय, जिसकी गुलामी में अमेरिका जी रहा था, पर दबाव बनाकर इस तरह के और अधिक पैसे जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिससे अमेरिका की समृद्धि का रास्ता बन्द हो गया।
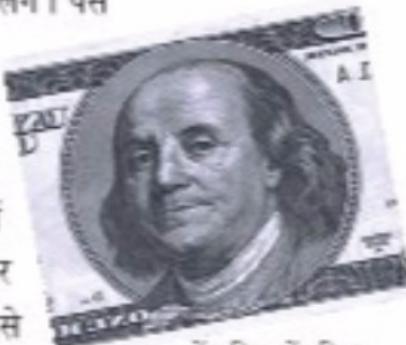
बेंजामिन फ्रेंकलिन

1764 में इंग्लैंड में एक और कानून बनने वाला था कि पहले से जारी किए गए कागज़ के नोट भी बन्द कर दिए जाएँ। इस कानून को रुकवाने के लिए जब बेंजामिन फ्रेंकलिन राजा जॉर्ज तृतीय से बात करने लन्दन गए तो उनकी मुलाकात बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक से हुई। फ्रेंकलिन ने लन्दन में बेरोज़गारी, गरीबी और अमीरों पर अत्यधिक टैक्स देखा तो निदेशक ने बताया कि यहाँ मज़दूर ज़्यादा हैं। यह जवाब फ्रेंकलिन को अटपटा लगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक द्वारा अमेरीका के गरीबों का हालचाल पूछने पर फ्रेंकलिन ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और उसे इतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीज़ें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुँच जाती हैं। इस तरह स्वयं का पैसा बनाकर हम ना सिर्फ उनकी क्रय शक्ति (purchasing power) तय करते हैं बल्कि हमें कोई ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ता।

24
आजाद्दी की लड़ाई (1776)

फ्रैंकलिन के बातचीत करने के बावजूद इंग्लैंड के बैंकरों के दबाव में अमेरिका में कानून बनाकर कागजध्के पैसों पर रोक लगा दी गई। इससे अमेरिका में एकाएक गरीबी और बेरोजघारी बढ़ गई और मन्दी का दौर आ गया। जिससे परेशान होकर अमेरिका के किसानों ने विद्रोह कर दिया। कई लोगों ने लिखा है कि अमेरीका की आजाद्दी की लडाई के पीछे एक मुख्य कारण यह था कि राजा ने उनके पैसे बनाने की आजाद्दी पर रोक लगाकर उन्हें गरीब बना दिया था। युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने कॉन्टीनेंटल नाम की कागज़ी मुद्रा जारी की और ताकतवर हो गए, जिससे वे इंग्लैंड से जीत गए और आजाद्द हो गए। परन्तु बाद में बैंकर्स ने उसके जैसे दिखने वाले नकली नोट बनाकर इसे व्यर्थ साबित कर दिया।

अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थॉमस जेफरसन के अनुमान से 200 मिलियन डॉलर की कॉन्टीनेंटल मुद्रा में लगभग इतना ही नकली पैसा बनाकर इसकी मात्रा दुगनी कर इसकी कीमत गिरा दी गई थी।

25
अमेरीका के शुरुआती केन्द्रीय बैंक

प्रथम केन्द्रीय बैंक (1791-1811)

कॉन्टीनेंटल मुद्रा षड्यंत्रकारी तरीके से व्यर्थ साबित करने के बाद इन लोगों ने अमेरिका के नेताओं को समझाया कि अपना खुद का पैसा बनाने से काम नहीं चलेगा और अमेरिका में भी बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसा एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की सलाह दी। अमेरिका के प्रथम केन्द्रीय बैंक की स्थापना 20 साल के चार्टर पर 1791 में हुई। थॉमस जेफरसन 1801 में अमेरिका का राष्ट्रपति बने और वे 1809 तक राष्ट्रपति रहे। उसने इस व्यवस्था को समझ लिया और केन्द्रीय बैंक को बन्द करवाने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी। परन्तु 20 साल का चार्टर होने के कारण यह 1811 तक चला।

जेफरसन कहते हैं, **"अगर अमेरिका के लोग बैंकों के माध्यम से पैसे का नियंत्रण होने देंगे तो बैंक और उनके आसपास विकसित कार्पोरेशन पहले महँगाई से फिर उसके बाद मन्दी से लोगों को उनकी सभी सम्पत्ति से वंचित कर देंगे, जब तक उनके बच्चें उनके पिता के कब्ज़े वाले महाद्वीप पर बेघर न उठें।"**

थॉमस जेफरसन

एक बयान में वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि बैंकिंग संस्थाएँ हमारी स्वतंत्रता के लिए दुश्मन की सेनाओं से भी बड़ा खतरा है। मुद्रा जारी करने का अधिकार बैंकों से छीनकर लोगों को दे देना चाहिए जिसके वे सच्चे अधिकारी हैं।

एक और अन्य बयान में वे कहते हैं कि काश संविधान में सिर्फ एक बदलाव करना सम्भव हो - केन्द्र सरकार से पैसे उधार लेने की शक्ति छीन लेना।

26

द्वितीय केन्द्रीय बैंक और राष्ट्रपति जैक्सन पर हमला

किन्तु 5 वर्ष पश्चात ही 1816 में बैंकर्स अपना द्वितीय केन्द्रीय बैंक स्थापित करने में सफल हो गए। इसे भी 20 साल का चार्टर मिला। 1829 में एन्ड्रयु जैक्सन यह घोषित करते हुए राष्ट्रपति बने कि वे केन्द्रीय बैंक को समाप्त कर देंगे। बैंकर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन्हें राष्ट्रपति ना बनने दिया जाए परन्तु वे एक बार नहीं दो बार राष्ट्रपति बने। 1836 में बैंक का चार्टर समाप्त होने वाला था और जैक्सन ने उसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया।
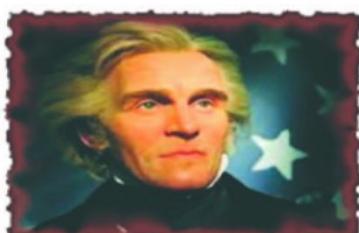
एन्ड्रयु जैक्सन

जैक्सन लिखते हैं, **"अगर अमेरिका के लोग मात्र मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था के अन्याय को समझ पाते तो कल सुबह होने से पहले क्रान्ति हो जाएगी।"** जैक्सन को 2 बार मारने की कोशिश हुई पर वह बच गया। जनवरी 1835 में आखिरी बार अमेरिका अपना कर्ज चुकाकर कर्ज मुक्त हुआ और द्वितीय बैंक का अन्त हुआ।

27

अब्राहम लिंकन का करिश्मा और हत्या (1863-65)

27 वर्ष की गुप्त योजना के बाद बैंकर्स सक्रिय हुए और 1863 में श्वेतों और अश्वेतों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। लड़ाई जीतने के लिए सेना को धन चाहिए था पर सरकार के पास पैसों की कमी थी। जब अब्राहम लिंकन इन बैंकर्स के पास कर्ज माँगने गए तो उन्हें 24 से 36 प्रतिशत ब्याज अदा करने को कहा गया। निराश होकर लिंकन वापस आ गए। अगर युद्ध नहीं लड़ते तो अमेरिका के दो टुकड़े हो जाते और अगर कर्जा लेकर लड़ते तो कर्ज के बोझ तले दब जाते।

राष्ट्रपति लिंकन के सामने एक धर्मसंकट आ गया था। उनके सचिव ने इस निराशा का कारण जानकर पूछा कि आप स्वयं का पैसा क्यों नहीं छापते। लिंकन ने पूछा, **"क्या हम सच में छाप सकते हैं?"** जवाब मिला, **"किसने मना किया है।"** तुरन्त लिंकन ने 500 मिलियन डॉलर छापे। जिनके पीछे का रंग हरा होने के कारण उनको 'ग्रीन बैक' कहा गया।

लिंकन युद्ध जीत गए। इस बात से विश्व में खलबली मच गई। लन्दन टाइम्स में 1865 में लेख आया कि **अगर उत्तरी अमेरिका की यह शरारती वित्तीय नीति स्थिरता के निष्कर्ष तक पहुँच जाती है तो सरकार बिना लागत के अपने खुद के पैसे बनाएगी। वो अपना सारा कर्ज चुका देगी और ऋणमुक्त हो जाएगी। अपना कारोबार चलाने के लिए इसके पास खूब पैसा होगा। यह दुनिया के सभ्य सरकारों के इतिहास में मिसाल से परे समृद्ध हो जाएगी। सभी देशों का धन और दिमाग अमेरिका चला जाएगा। यही कारण है कि इस सरकार को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया की हर राजशाही को नष्ट कर देगी।** 1865 में ही लिंकन की हत्या हो गई।

28
राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या (1881)

1881 में जेम्स गारफील्ड अमेरीका के राष्ट्रपति बने और वे साहसपूर्वक बैंकर्स के खिलाफ खड़े हुए। इसी कारण उनकी हत्या हो गई। एक बयान में वे कहते हैं कि, **"जिस किसी ने भी देश में पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया है, वह सभी उद्योग और वाणिज्य का पूर्ण स्वामी बन गया है। जब आप पाएँगे कि पूरा सिस्टम शीर्ष पर बैठे कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा बहुत आसानी से नियंत्रित किया जाता है तो महँगाई और मन्दी क्यों आती हैं बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी।"**

राष्ट्रपति बनने के चार महीने के अन्दर ही उनकी हत्या हो गई। मन्दी गहरा गई, जनता बेरोज़गारी, गरीबी और भुखमरी के दलदल में फँस गई।

फसलें खेत में सड़ने के लिए छोड़ दी गईं क्योंकि ना तो मज़दूरों को देने के लिए पैसा था और न ही खरीदने के लिए बाज़ार में कोई ग्राहक था। देश में सब कुछ होते हुए भी गरीबी थी क्योंकि व्यापार का चक्का चलाने के लिए पैसे की कमी थी। देश को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, पर बैंकरों ने दबाव बनाया कि सरकार खुद के पैसे छाप लेगी तो महँगाई और बढ़ जाएगी।

जेम्स गारफील्ड

29
बड़े खेल की शुरुआत

जैकल द्वीप

बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से केन्द्रीय बैंक बनाने की कोशिशें तेज़ी से शुरू हुईं। 1907 में अफवाह फैलाई गई कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं, जिससे लोगों ने अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया और सच में ही बैंक फेल होना शुरू हो गए। समाधान के रूप में बैंकर्स ने सरकार को एक केन्द्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया और 1910 में जैकल द्वीप पर बैंकर्स ने एक खुफिया बैठक करके एक कानून की रूपरेखा बनाई जिसे अमेरिका की संसद में पास कराना था।

बैंकों से पैसे निकलवाने के लिए एकत्र भीड़
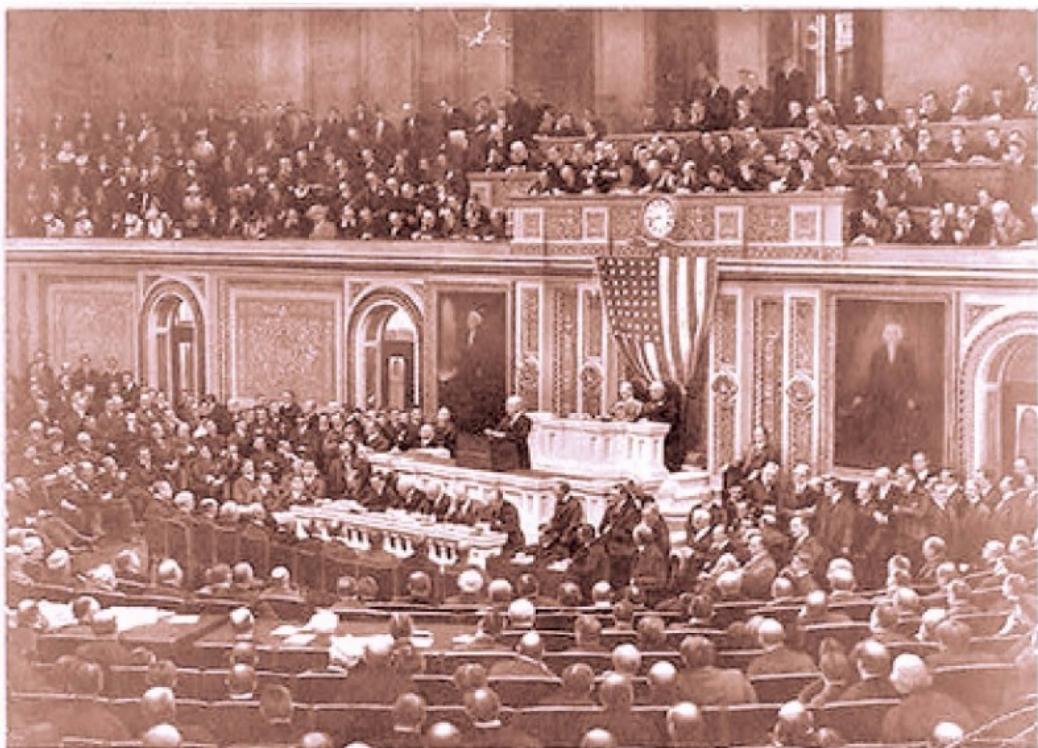
30

फेडरल रिजर्व एक्ट, 1913

वुड्रो विल्सन को राष्ट्रपति पद कि लिए चुनाव में आर्थिक मदद के बदले फेडरल रिजर्व एक्ट (Federal Reserve Act) नाम का कानून पास करने को कहा गया। नाम में 'फेडरल' शब्द भ्रमित करने के लिए रखा गया ताकि जनता को लगे कि इसका सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है। 23 दिसम्बर 1913 को जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे, सरकार ने अमेरीका की गुलामी का यह कानून पास कर दिया।

वुड्रो विल्सन

बाद में विल्सन ने पश्चाताप में लिखा, **"हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केन्द्रित है। इसलिए, देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियाँ कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हैं। हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है।"**

31

फेडरल रिजर्ष का मालिक कौन?

अमेरिका का केन्द्रीय बैंक, फेडरल रिजर्ष वास्तव में एक स्वतंत्र और निजी कम्पनी है जिसके लगभग 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्ष बैंक हैं। इनकी मालकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है। फेडरल रिजर्ष बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा रखते हैं और न्यू यॉर्क की फेडरल रिजर्ष बैंक के पास पूरे फेडरल रिजर्ष सिस्टम की 53 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। 1997 में न्यू यॉर्क फेडरल रिजर्ष की रिपोर्ट थी कि चेजय्मैनहैटन बैंक, सिटी बैंक और मोरगन गारंटी ट्रस्ट कम्पनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। 2000 में जे.पी. मोरगन और चेजय्मैनहैटन एकत्रित होकर जे.पी. मोरगन चेजय्कम्पनी बन गए। सिटी ग्रुप रॉकफेलर साम्राज्य का ही एक हिस्सा है।

32
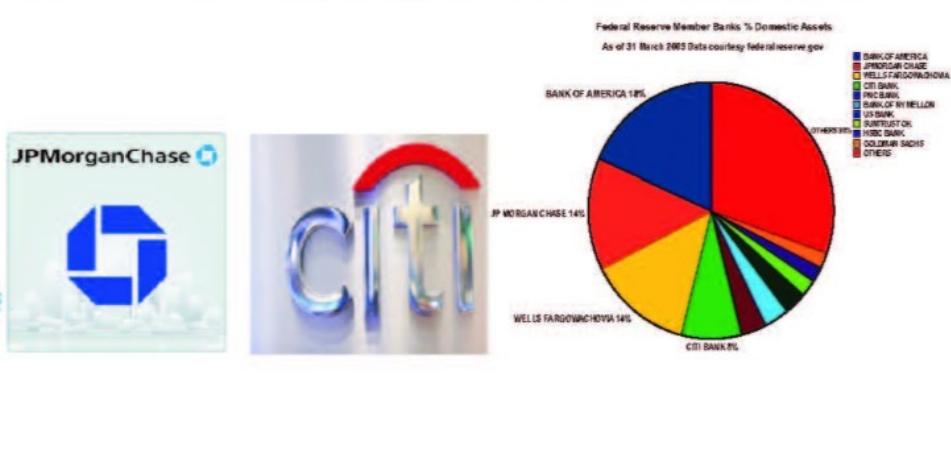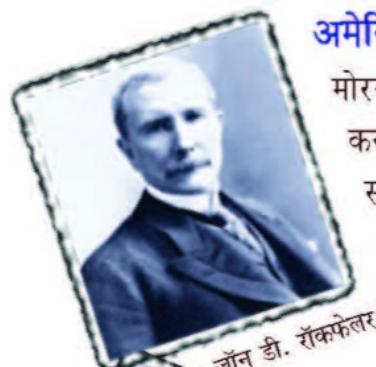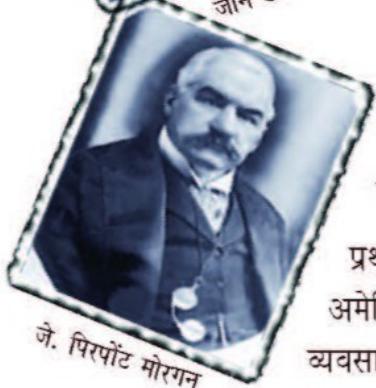
रॉकफेलर और मोरगन की कहानी

अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटेरे थे, परन्तु जे. पिरपोंट मोरगन, एँड्रयू कारनेज और जॉन डी. रॉकफेलर ही नेतृत्व करते थे। मोरगन का दबदबा वित्त पर था, कारनेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। मोरगन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया, बल्कि खरीदा था और उसे प्रतिस्पर्धा से घृणा थी। 1901 में मोरगन ने कारनेज से खरीदी हुई मीलों से अरबों डॉलर की पहली कम्पनी यू.एस. स्टील बनाई। रॉकफेलर ने भी अपने प्रतिद्वन्दियों को खरीदकर निपटा दिया और उसकी कम्पनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी बनी।

जॉन डी. रॉकफेलर

जे. पिरपोंट मोरगन

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले अमेरिका के वित्त और व्यवसाय का आधार मोरगन की फाइनेंस और यातायात तथा रॉकफेलर की तेल कम्पनी ही थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में गठबन्धन हो गया। यह कहा जाता है कि आपसी तालमेल से अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था को ये ही नियंत्रित कर रहे थे।

पहले रॉकफेलर और मोरगन एक-दूसरे के दुश्मन थे। यह प्रतिस्पर्धा राजनैतिक सत्ता

प्राप्ति के लिए थी। परन्तु उन दोनों को ही ब्रिटिश वित्तदाता से, यानी रोथशिल्ड से पूरा सहयोग मिलता था। चेजघ्बैंक रॉकफेलर द्वारा ख़रीदा गया, जिसे रोथशिल्ड ने वित्तीय सहायता की थी। ये पैसे न्यू यॉर्क की एक बैंकिंग फर्म 'कुहन, लोएब एंड कंपनी' के माध्यम से आए थे, जो कि जर्मनी के एक अप्रवासी जैकब स्किफ के नियंत्रण में थी। स्किफ ने ये हिस्सेदारी रोथशिल्ड की वित्तीय मदद से बनाई थी। बाद में उसने कुहन को खरीद लिया और लोएब की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। मैनहैटन कंपनी भी कुहन, लोएब और वारबर्ग्स के बैंकिंग हित के माध्यम से रोथशिल्ड के नियंत्रण में आ गई। इस तरह एक और बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया। 1955 में रॉकफेलर के चेजघ्बैंक का विलय मैनहैटन कंपनी के साथ हुआ, जो 'चेजघ्मैनहैटन बैंक' बना।

जैकब स्किफ

मोरगन परिवार की सभी बैंकिंग गतिविधियों का भी सीधे तौर पर इंग्लैंड से पता लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट के बुरे दौर में भी मोरगन का बैंक उच्च पायदान पर रहता था, यह इस बात की पुष्टि करता है। बैंकों के बुरे दौर (1873, 1884, 1893 और 1907) में, जब अन्य सभी बैंक घाटे में चल रहे थे, मोरगन के बैंकों ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाए रखा और पैसे की व्यवस्था बनाए रखी।

स्किफ परिवार

33
प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18)

प्रथम विश्वयुद्ध इंग्लैंड और जर्मनी में शुरू हुआ। अमेरीका का इससे कोई लेना-देना नहीं था। पर बैंकर्स अपने बेहिसाब फायदे के लिए अमेरीका को युद्ध में घसीटना चाहते थे। अमेरीका के राज्य सचिव विलियम जेनिंग्स कहते हैं, **"बड़े बैंकिंग हित विश्वयुद्ध में गहरी रुचि रखते थे, क्योंकि इसमें बड़े लाभ के लिए व्यापक अवसर थे।"** इस युद्ध से अकेले रॉकफेलर ने उस समय 20 करोड़ डॉलर कमाए, जबकि युद्ध का खर्च 3,000 करोड़ डॉलर आया और करोड़ों लोग मारे गए और बर्बाद हो गए।

एक बातचीत जो ग्रे (इंग्लैंड के विदेश सचिव) और हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का प्रमुख सलाहकार) के बीच हुई जो बाद में सार्वजनिक हुई।

ग्रे: इंग्लैंड के विदेश सचिव
अमेरिका के लोग क्या करेंगें अगर जर्मन एक समुद्री जहाज डूबा दें जिसपर अमेरिका के नागरिक हों?

लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्री सीमा में भेजा गया और उन्होंने वह जहाज डुबो दिया जिसमें 1,200 लोग मारे गए। इसका बहाना लेकर अमेरिका भी विश्वयुद्ध में कूद पड़ा। जबकि इसके पीछे का असली खेल बैंकर्स का था।
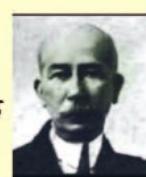
34
रूस की क्रान्ति (1917)

ट्रॉट्स्की

रूस की ताकत अमेरिका से ज़्यादा होने लगी थी और तेल का उत्पादन भी अमेरिका से ज़्यादा होने लगा था। बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए 'लीग ऑफ नेशंस' बनाना चाहते थे। परन्तु जब उन्होंने यह गुप्त योजना रूस के राजा (जार) के साथ साझा की तो उसने इसे समर्थन नहीं किया और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया। इससे बैंकर्स की नजर में वो खटकने लगा। फरवरी 1917 में रूस में एक जनविद्रोह हुआ और क्रान्ति हो गई। यह क्रान्ति शान्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी। परन्तु बैंकर्स ने जर्मनी सरकार के माध्यम से लेनिन और ट्रॉट्स्की के प्रति क्रान्ति के लिए दो बिलियन डॉलर की मदद की। जिसके बाद नवम्बर में रूस में क्रान्ति और साम्यवाद (कम्यूनिज़्म) के नाम पर खूनी क्रान्ति के माध्यम से बैंकर्स के ऐजेंट सत्ता में आ गए।

क्रान्ति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूज़ीन लियोन्स ने लिखा है, **"लेनिन, ट्रॉट्स्की और उनके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका; उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका, जिसे मार्च 1917 में हुई एक लोकप्रिय क्रान्ति के माध्यम से स्थापित किया था।"** पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त व्यापार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हेरफेर के लिए खुला छोड़ दिया।

1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस प्रणाली को 'पैसे बिना अर्थव्यवस्था' के कम्युनिस्ट विचार के विरुद्ध जाकर 1920 में भंग कर दिया गया। जिसके बारे में एडवर्ड ग्रिफिन अपनी पुस्तक 'द क्रेएचर फ्रॉम जैकिल आइलैंड' में लिखते हैं **"1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अन्तरराष्ट्रीय बैंक का गठन किया। इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धान्त के अनुसार राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों के एक गिरोह द्वारा संचालित था। इनमें न केवल जार के पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडिश, जर्मन और अमेरिकी बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।**

विदेशी पूँजी का हिस्सा अधिकांश इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार से आया था। नए बैंक के विदेश प्रभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त मैक्स मई, न्यू यॉर्क में मोरगन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी के उपाध्यक्ष थे। अक्टूबर क्रान्ति के तुरन्त बाद के वर्षों में ब्रिटिश और अमेरिकी कारोबार के लिए सोवियत संघ द्वारा जारी किए गए बड़े और आकर्षक (गैर प्रतिस्पर्धी) ठेकों का एक सतत सिलसिला वहाँ देखा जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन भेड़ियों को जल्द ही नए सोवियत शासन के लाभ का एक उपहार मिला।"

एंटनी सी. स्टन अपनी किताब 'वालस्ट्रीट एड द बोल्शेविक रिवोल्यूशन' में इसके सारे सबूत प्रस्तुत करते हैं। लेनिन की मृत्यु के पश्चात स्टालिन सत्ता में आ गए और वो सही मायने में कम्युनिस्ट थे। सत्ता में आते ही स्टालिन ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकर्स को नियंत्रण में रखा।
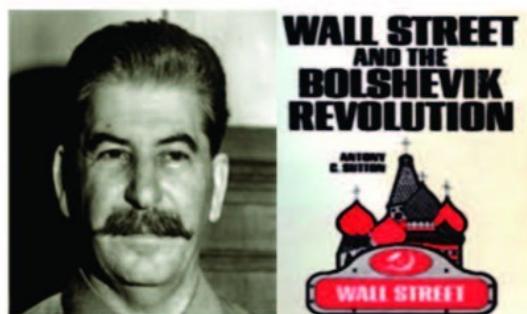
स्टालिन

35

संस्थाओं की स्थापना

युरोपीय संघ के वास्तुकार जीन मॉन्नेट ने एक बार लिखा था, **"मनुष्यों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थानों के बिना कुछ भी स्थाई नहीं होता।" जब मानव-जाति असफल होती है, तब अच्छी संस्थाएँ इसे बचाती हैं।**

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी अब उन्होंने विश्व नियंत्रण का सपना देखा और 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर "लीग ऑफ नेशंस" बनाया, जो बाद में "संयुक्त राष्ट्र संघ" बना। अमेरिका की विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए 1919 में ही 'काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन' (CFR) बनाया जो अमेरिका सरकार के नियंत्रण में न होकर बैंकर्स का एक गुप्त समूह था। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में बिना किसी संगठन के बैनर तले एक खुफिया बैठक चल रही थी। इस समुह का कोई नाम नहीं था इसलिए

इसका नाम बिल्डरबर्ग समूह पड़ गया। यह बैंकर्स का दुनिया का सबसे खुफिया समूह माना जाता है, जहाँ से दुनिया की दशा और दिशा तय होती है। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का एक ट्राईलेट्रेल कमिशन (त्रिपक्षीय आयोग) बना जिसमें बाद में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इस तरह के कुछ और खुफिया समूह आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण करते हैं, जहाँ बैठकर दुनिया का वर्तमान और भविष्य तय किया जाता है।

36

महामन्दी (1929-33)

प्रथम विश्वयुद्ध के तत्काल बाद फेडरल रिजर्व द्वारा अचानक ब्याज दरें बढ़ा दी गईं, जिससे पैसे की कमी हुई और मन्दी आ गई। किन्तु रणनीति बदलकर 1920 के अन्त से 1929 तक सस्ता कर्ज देकर अमेरिका में पैसे की मात्रा को 62 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा लगाएँ इसलिए शेयर का मात्र 10 प्रतिशत राशि देकर खरीदने या बेचने के नियम बनाए गए। लोगों ने अपनी जमीन तक बेचकर अपना सारा धन इस जुए में लगा दिया क्योंकि उस समय हर कोई इससे लाभ उठाता दिख रहा था।

जब लोगों का सारा पैसा इस जुए में लगा था, तो बैंकरों ने 29 अक्टूबर 1929 को अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर इसे क्रेश करा दिया। लोगों की सारी सम्पति एक दिन में ही लुट गई। बाकी शेष कसर ब्याज दरें बढ़ाकर पैसे की कमी कर मन्दी लाकर कर दी गई। 1929 से 1933 तक महामन्दी का दौर रहा जिसमें हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए। बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई और आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू हो गए। भीख माँगकर खाना तक मुश्किल हो गया था।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे मिल्टन फ्राईडमैन लिखते हैं, **"फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929-1933 में देश में मुद्रा संचालन को एक तिहाई कम करके महामन्दी (ग्रेट डिप्रेशन) को जन्म दिया है।"**

मिल्टन फ्राईडमैन

अमेरिकी काँग्रेस (संसद) सदस्य चार्ल्स मैकफेडन लिखते हैं, **"महामन्दी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिससे वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सकें।"**

चार्ल्स मैकफेडन ने बैंकर्स के विरुद्ध बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जह्र की वजह से वे अमेरिकी संसद में ही मर गए। 10 जून 1932 को उनका एक बयान, **"कुछ लोगों को लगता है कि फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिकी सरकार की संस्थान हैं। पर ऐसा नहीं है। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी शक्तियों को छुपाने के हर सम्भव प्रयास किए गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फेडरल रिजर्व ने सरकार को कब्जा लिया है। यह यहाँ सब कुछ नियंत्रित करता है और हमारे सारे विदेशी सन्बन्धों को भी नियंत्रित करता है। यह सरकार बनाता है और गिराता है।"**

चार्ल्स मैकफेडन

37
गोल्ड स्टैंडर्ड का अन्त (1933)

1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने के लिए और सभी का सोना लूटने के लिए 10 वर्ष की जेल का डर दिखाकर लोगों से सारा सोना हथिया लिया। तुरन्त बाद सोने की कीमतें 3 गुना बढ़ा दी गईं और जनता के हाथ में सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह गए।

आज भी अधिकतर लोग और यहाँ तक कुछ कम पढ़े-लिखे अर्थशास्त्री भी यही मानते हैं कि पैसा अभी भी सोने के आधार पर बनता है परन्तु यह बात 1933 के बाद लागू नही है और लोग अभी भी पिछली सदी में जी रहे हैं।

POSTMASTER: PLEASE POST IN A CONSPICUOUS PLACE.—JAMES A. FARLEY, Postmaster General

UNDER EXECUTIVE ORDER OF THE PRESIDENT

Issued April 5, 1933

all persons are required to deliver

ON OR BEFORE MAY 1, 1933

all GOLD COIN, GOLD BULLION, AND GOLD CERTIFICATES now owned by them to a Federal Reserve Bank, branch or agency, or to any member bank of the Federal Reserve System.

Executive Order

नोट - सोने का पूरा रहस्य अगली पुस्तक में विस्तार से समझाया जायेगा।

38
जॉन एफ. कैनेडी (1961-63)

अब्राहम लिंकन के खुद के पैसे बनाने के 100 साल बाद एक और राष्ट्रपति ने उनके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश की। 4 जून, 1963 को कैनेडी ने एक कार्यकारी आदेश 11110 पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश से अमेरिका के राष्ट्रपति को देश चलाने के लिए कर्जमुक्त पैसे बनाने का अधिकार मिल गया। उसने फिर फेडरल रिज़र्व को अनदेखा करते हुए अमेरिकी सरकार के 4 अरब डॉलर बनाए, जिसकी आज की कीमत 60 अरब डॉलर (लगभग 4 लाख करोड़ रुपए) है। एकाएक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जीवन मिल गया। इसके बाद वे फेडरल रिज़र्व को ही समाप्त करना चाहते थे परन्तु इससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

उनकी हत्या के बाद आदेश 11110 को निरस्त कर दिया गया।

एक भाषण में राष्ट्रपति कैनेडी कहते हैं, "देवियों और सज्जनों, 'गोपनीयता' एक मुक्त और खुले समाज के विरुद्ध है, और हम लोग स्वाभाविक और ऐतिहासिक तौर से षड़यंत्रकारी समूह, रहस्यमयी शपथ और गुप्त कार्यवाही करने के विरोधी रहे हैं। आज हम सभी कुछ षड़यंत्रकारियों का शिकार हुए हैं, जो अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए मुख्य रूप से गुप्त योजनाओं पर निर्भर करते हैं। ये लोग आक्रमण की बजाय घुसपैठ पर, चुनाव की बजाय धमकी पर, स्वतंत्रता के विकल्प की बजाय तोड़फोड़ पर विश्वास करते हैं। इन्होंने मानव और भौतिक संसाधनों को लेकर एक अत्यधिक कुशल सिस्टम बनाया है जिसमें सैन्य, कूटनीतिक, खुफिया, बौद्धिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक ताकतें जुड़ी हैं। इनकी तैयारी गुप्त रखी जाती हैं, प्रकाशित नहीं होती। इनकी गलतियों को दफन किया जाता है, हैडलाइन नहीं बनने दिया जाता। उनसे असन्तुष्ट लोगों को खामोश किया जाता है, उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। ना ही किसी खर्च पर सवाल उठाया जाता है, ना ही कोई रहस्य खोला जाता है। इसलिए मैं अमेरिका के लोगों को जानकारी देने और सतर्क करने के जबरदस्त काम में आपकी मदद माँग रहा हूँ; ताकि आपकी मदद से, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, आदमी वही बनेगा जिसके लिए वह पैदा हुआ है - स्वतंत्र और स्वावलम्बी।"

जॉन एफ. कैनेडी

हत्या के 7 दिन पहले उनका एक बयान है, "इस देश में हर आदमी, औरत और बच्चे को गुलाम बनाने का षड़यंत्र चल रहा है, जिसे मैं अपना पद छोड़ने से पहले उजागर कर दूँगा।"

39
जर्मनी (1919-45)

जर्मनी ही एक ऐसा देश था जिसने सही मायने में हिटलर के नेतृत्व में बैंकरों को चुनौती देने की जुर्रत की थी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो गया। जर्मनी को युद्ध का पूरा खर्च भरना था, जो पूरे देश की सम्पत्ति से तीन गुणा था। जर्मनी के केन्द्रीय बैंक का निजीकरण कर दिया गया। इसके बाद बेहिसाब पैसे बनाकर शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध करा दिए। (शॉर्ट सेल प्रक्रिया को डॉलर राज के साथ अगली पुस्तिका में समझाया जाएगा।)

Wholesale Price Index	
July 1914	1.0
Jan 1919	2.6
July 1919	3.4
Jan 1920	12.6
Jan 1921	14.4
July 1921	14.3
Jan 1922	36.7
July 1922	100.6
Jan 1923	2785.0
July 1923	194,000.0
Nov 1923	726,000,000,000.0

इससे 1922-23 में जर्मनी में भयंकर आर्थिक संकट आया जिससे बेहिसाब महँगाई बढ़ी। इसे हाइपर इन्फ्लेशन (Hyperinflation) कहते हैं। जर्मनी में थोक मूल्य सूचकांक एकाएक बढ़ गया जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। सुबह से शाम तक चीज़ों के दाम दोगुने हो जाते थे। एक समय पर एक डॉलर की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक हो गई थी। नोटों की गड्डियाँ व्यर्थ हो गई थीं, जिससे बच्चे घर बनाने जैसे खेल खेलते थे, जिसे आप तस्वीर में देख पा रहें हैं। फ्रैंक की कीमत इतनी गिर गई थी की जर्मनी को 100 लाख करोड़ फ्रैंक तक का नोट छापना पड़ा। इस पूरी परिस्थिति के ज़िम्मेदार बैंकर ही थे।

नोटों की गड्डियों से खेलते बच्चे

हिटलर द्वारा जारी बांड

रूस के शासक स्टालिन के विरुद्ध बैंकरों ने हिटलर को खड़ा किया, परन्तु बाद में हिटलर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया; क्योंकि उसने जर्मन बांड बैंकों में ना देकर सीधे लोगों में खर्च करने शुरू कर दिए। हिटलर ने जर्मनी के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ के जर्मन बांड जारी किए, जिनको लेबर ट्रेजरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। लाखों लोगों को काम पर लगाया गया और सभी को ट्रेजरी सर्टिफिकेट से भुगतान किया गया। जब कर्मचारियों ने ये सर्टिफिकेट वस्तुओं और सेवाओं के बदले जनता में खर्च किए तो और ज़्यादा लोगों को ज़्यादा काम मिलने लगा।

2 सालों में ही बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो गई और देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उनके पास एक मजबूत और टिकाऊ मुद्रा थी और महँगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मन्दी झेल रही थी, युद्ध में बर्बाद हुआ जर्मनी विश्व महाशक्ति बनने जा रहा था। बैंकरों ने बैंकों के एकाएक दिवालिया होने की भविष्यवाणी की, पर गलत साबित हुए। बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की आय बहुत अधिक बढ़ गई। जर्मनी समृद्ध हो गया।

40
हिटलर (1933-45)

हिटलर के बारे में एक व्यक्ति लिखते हैं जर्मनी ने बिना सोने के और बिना किसी ऋण के 1935 से 1945 के लिए अपनी पूरी सरकार और युद्ध आपरेशन का खर्च उठाया। यूरोप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने के और यूरोप को वापस बैंकरों की एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूँजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा। परन्तु यह इतिहास किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं पढ़ाया जाता।

हिटलर स्वंय कहता है, "अगर जरूरत कभी लोगों की आँखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी हैं, तो वे देखेंगे कि इसी जरूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण पूँजी का पूरा उपयोग करना सिखा दिया है, जो कि है किसी भी राष्ट्र के कार्य (श्रम) की पूँजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भण्डार के सभी विचार सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योग के सामने बौने साबित होते हैं।"

41

द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-45)

क्योंकि हिटलर ने अपना पैसा जारी किया, इसलिए वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। हिटलर को रोकने के लिए और बेहिसाब धन कमाने के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध करवाया गया। जबकि हिटलर युद्ध नहीं करना चाहता था, उसे युद्ध में उतारा गया।

मुसोलिनी और हिटलर

जिसके बारे में बेडफोर्ड के राजकुमार हास्टिंग्स रस्सल ने बयान दिया, **"पूँजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और**

हिटलर की सेना

अधिक केन्द्रित करने के लिए युद्ध चाहते हैं। हिटलर ना सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुएँ बनाने की क्षमता है, ना कि जब लोग और माल दोनों हों पर पैसों के अभाव के कारण राष्ट्रहित के काम अधूरे रह जाएँ। यह ब्रिटेन और अमेरिका के पूँजीपतियों की नजर में अधर्म था अगर उसे फैलने दिया जाता तो वह उनकी जड़ें उखाड़ देता।"

42

आजाद्द हिन्द सरकार की करेंसी

सुभाष चन्द्र बोस और हिटलर

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को हिटलर से मिलने के बाद यह समझ में आया कि हिटलर की ताकत का असली राज़ उसके पैसे बनाने की शक्ति में छुपा है। इसलिए जब नेताजी ने आजाद्द हिन्द सरकार का नेतृत्व किया तो सबसे पहले "बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस" बनाकर अपनी स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू कर दिए। इससे आजाद्द हिन्द फौज का बल इतना बढ़ गया की वह अँग्रेजी़ साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतह करती चली आई। यही कारण था की अँग्रेजध्भारत को छोड़कर जाने के बाद नेताजी को और उनके स्वतंत्र पैसे बनाने के विचार को भारत में नहीं आने देना चाहते थे।

नेताजी के बारे में महत्वपूर्ण बातों में से यही वो एक बात है जो भारत सरकार देश की जनता से छिपाकर रखना चहती है।

43
भारत की कहानी
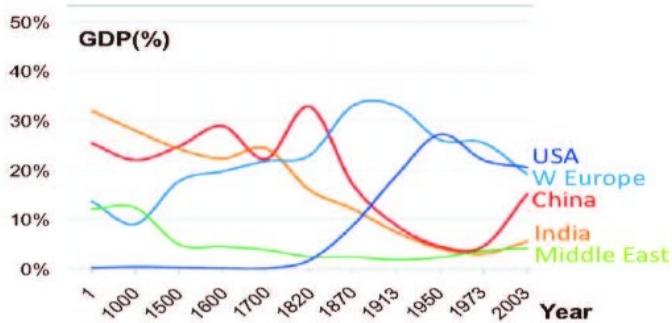
सन 1700 में अँग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4 प्रतिशत आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। भारत कृषि केन्द्रित एवं उद्योगप्रधान देश रहा है। अँग्रेजों से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोने-चाँदी के सिक्कों के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। राजा अगर कर भी लगाता था तो धर्म और जन-कल्याण के कार्यों के माध्यम से फिर से पैसा लोगों तक लौट आता था। राजा हर्षवर्धन तो हर वर्ष अपना सारा खजाना लोगों में बाँट देता था।

दादाभाई नारौजी ने भी अँग्रेजों द्वारा भारत की लूट को अपनी पुस्तक 'पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में दर्शाया है। उन्होंने समझाया कि अँग्रेजों ने सारा कर फसल के एक हिस्से की बजाय सोने-चाँदी में लगा दिया और सारा धन बाहर ले गए। किसान को अब सारा कर सोने में देना था, फसल बर्बाद होने पर ऋण लेकर उसे भरना होता था, इसलिए वह कर्ज के बोझ तले दब गया। इससे मुद्रा की मात्रा में कमी आई (short money) और भारत के कृषि और उद्योग नष्ट हो गए। भारत गरीबी के कुचक्र में फँस गया।
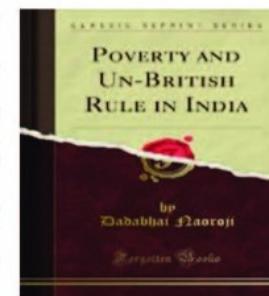
अँग्रेजों ने जाने से पहले इस देश में आर्थिक गुलामी को बरकरार रखने के लिए सन् 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। वर्ष 1947 में देश को तथाकथित रूप से आजाद्ध कर अपनी व्यवस्था ज्यों की त्यों छोड़ दी।

THE TIMES OF INDIA

14 TOP BANKS ARE NATIONALISED

Ordinance follows unanimous Cabinet decision

'Syndicate' in disarray as Morarji goes

A vital step, says Indira

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की खबर

भारत के आजाद्ध होने के बाद 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, परन्तु बैंकों की व्यवस्था यथावत रही। जॉन एफ. कैनेडी द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए मशहूर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गालब्रेथ की सलाह पर 1969 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

इन्दिरा गाँधी को लेकर 1971 में अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैनरी किसिंजर की बातचीत, जिसे अमेरिका की सरकार ने 2005 में सार्वजनिक कर दिया -

राष्ट्रपति निक्सनः **"इस मामले में इन्दिरा गाँधी कुतिया है।"**

किसिंजरः **"हाँ, भारतीय हरामी होते हैं।"**

राष्ट्रपति निक्सनः **"भारत को ज़रूरत है एक और युद्ध की। सालों को एक युद्ध लड़ने दो।"**

अमेरिका की मदद पाकर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, पर बुरी तरह से हारा और उसके दो टुकड़े हो गए। युद्ध के दौरान तेल कम्पनियों ने अमेरिका के इशारों पर काम करते हुए भारत की मदद करने से इनकार कर दिया जिसके बाद इन्दिरा ने तेल कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1973 में भारत को कोई व्यापार घाटा नहीं था और उसके पास प्रयाप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भण्डार था। 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कमी बताकर तेल कीमतें चार गुना कर दी गई। भारत के पास विदेशी मुद्रा भण्डार 629 मिलियन डॉलर था जबकि तेल

जयप्रकाश नारायण

हैनरी किसिंजर और इन्दिरा गाँधी

का आयात 1,241 मिलियन डॉलर हो गया। भारत को विदेशी कर्ज लेना पड़ा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने कई शर्तें लगा दी।

इन्दिरा गाँधी के भ्रष्टाचार के विरोध में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक व्यापक आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलन की शुरुआत छात्र आन्दोलन से हुई थी। जयप्रकाश नारायण तो स्वयं ईमानदार थे, परन्तु अमेरिका के सहयोग से कुछ गलत लोग आन्दोलन में आ गए। 1977 में इन्दिरा गाँधी सत्ता से बाहर हो गईं और अमेरीका के मित्र सत्ता में आ गए। प्रसिद्ध लेखक इंगदाल लिखते हैं, **"हैनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था, ब्रिटिश के गहरे समन्वय के साथ।"**

1991 में राजीव गाँधी की मृत्यु के पीछे भी उन्ही लोगों का हाथ था, क्योंकि राजीव गाँधी उनका साथ नहीं दे रहे थे। 1991 में भारत में आर्थिक संकट खड़ा कर भारत को वैश्विकरण के कुचक्र में फँसा दिया गया। इसमें प्रमुख भूमिका रॉकफेलर के सिटी बैंक ने अदा की।

2004 से 2014 में मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश को खूब लूटा। अब कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह का नाम भी उजागर हुआ है। मनमोहन सिंह पहले विश्व बैंक में काम करते थे, बाद में इन लोगों ने उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनवा

दिया। एक समय ऐसा भी आया था कि सरकार किसी भी दल या गठबन्धन की बने, वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह का ही बनना तय था और अन्ततः ऐसा ही हुआ। **इस देश के प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव और विदेश सचिव जैसे पदों पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सहमति के बिना नहीं बैठ सकता।**

मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कालाधन आदि मुद्दों पर हुए आन्दोलन के कारण जनता, और खास तौर पर युवक-युवतियाँ, जागृत होकर सड़कों पर उतर आई थी। इसी लहर ने 2014 में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया परन्तु व्यवस्था परिवर्तन न करके वे भी जाने अनजानें में इन्हीं की व्यवस्था को आगे बढ़ा रहें हैं।

आप अखबारों की इन खबरों को पढ़ सकते है।

इस तरह से देश के संसाधनों को अगर विदेशों को बेच दिया गया तो इस देश को पुनः खड़ा कर पाना असम्भव सा हो जाएगा।

भूमि अधिग्रहण : लक्ष्य-किसान मुक्त भारत

भारत के किसानों की जमीन हथियाने और कृषि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के इरादे से अँग्रेजों ने 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था। इसकी वजह से इंग्लैंड के कारखानों और खेत मालिकों को काफी लाभ मिला था। लेकिन, भारतीय किसान लगातार उसके विरोध में लड़ते रहे हैं। 1947 के बाद भी यह कानून भारत में लागू रहा।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (सम्प्रग) सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को देखते हुए लगता था कि 2014 के चुनाव में इसकी करारी हार होने वाली है। सम्भावित हार से बचने और किसानों के संघर्षों के बाद अपनी सत्ता जाते देख भोले मतदाताओं के लुभाने के खयाल से 2013 में सरकार ने इसे कुछ हद तक बदलकर किसानों के हित में कर दिया।

काँग्रेस मुक्त भारत के बाद मोदी का अगला उद्‌देश्य था किसान मुक्त भारत। इसलिए 31 दिसम्बर 2014 को मोदी सरकार ने पूँजीपतियों के मार्गदर्शन में एक अध्यादेश जारी किया, जो 1894 के भूमि अधिग्रहण के काले कानून से भी अधिक खतरनाक था।

पैसे आने पर किसान अपना कर्जच्चुकाने में, घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई पर और कुछ लोग शराब और जुए में पैसा उड़ा देते हैं। इस तरह से एक दिन सारा पैसा और जमीन पूँजीपतियों की हो जानी है और किसान गरीब, बेरोजगार और भूमिहीन हो जाएगा।

चेतावनी रैली में अन्ना हजारे

ब्रिटेन और विश्व बैंक की एक परियोजना के लक्ष्य के अनुसार 2020 तक 2 करोड़ किसानों को विस्थापित करके भारत को एक निर्यात केन्द्रित, कॉर्पोरेट नियंत्रित, औद्योगिक कृषि मॉडल के लिए तैयार करना है। उनका तर्क है कि परम्परागत भारतीय किसान उत्पादक नहीं हैं और न ही वो बाजार के लिए खेती करते हैं।

इसलिए उन्हें खेती के काम से हटा देना ही बेहतर है। नतीजतन किसान आत्महत्या करेंगे या जमीन कार्पोरेट को सौंपकर शहरों में अकुशल मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर होंगे।

रवि कोहाड़
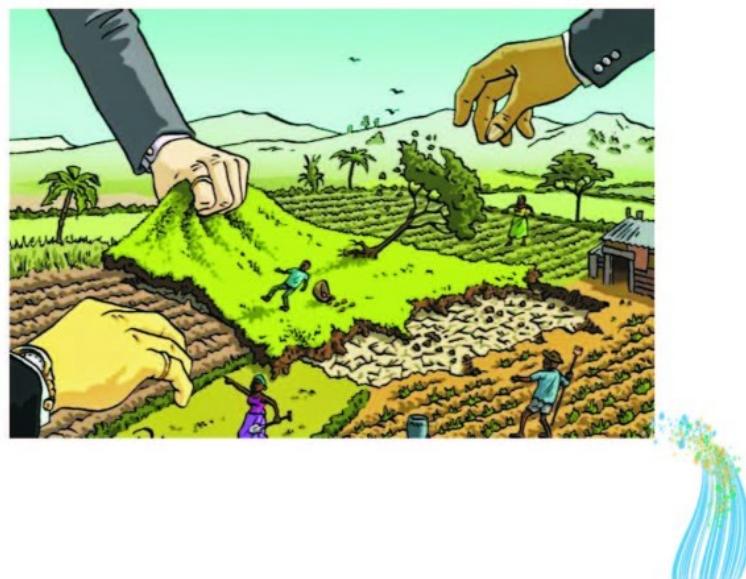
इस षड़यंत्र के विरोध में देश के तमाम संगठनों के साथ मिलकर अन्ना हजारे जी के मार्गदर्शन में 'युवा क्रान्ति' ने 24 फरवरी 2015 को हज़ारों किसानों के साथ दिल्ली के संसद मार्ग पर 'चेतावनी प्रदर्शन' किया, जिससे देश भर में इस काले कानून के विरोध मे एक लहर उठ खड़ी हुई।

अक्षय कुमार

45
बाबा रामदेव के दमन का असली कारण
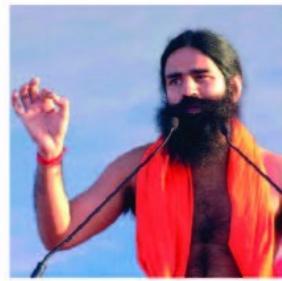
बाबा रामदेव ने बैंक व बैंकर्स के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया था, इसलिए जब उन्होंने काले धन के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया तो रात को आंदोलन का दमन कर दिया गया। उनका एक बयान जिसमें वे कहते हैं, **"ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें हैं ना, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगो से.... नेपोलियन व हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी-पूँजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक, एक है रोथशिल्ड और दूसरा है रॉकफेलर। और दोनों के ही संयोग से पाँच-पाँच बच्चे थे। और उससे जो है ये पूरी पूँजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतें खड़ी हुई।**

रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रोथशिल्ड पैदा हुआ। रोथशिल्ड.. अब रोथशिल्ड जो है यह यहूदी परम्परा में विश्वास रखता था। इसने बैंक और बैंकर्स.... ये जो करेंसी की व्यवस्था है, उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक.... और बैंकर्स, ये जो पूरा सिस्टम.... दुनिया की पूरी सम्पत्ति कहाँ जाती है अन्तोगत्वा? बैंकों में जाती है, और जो है सोने में जाती है। सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियाँ थी, पाँच जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया। और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने ज़िन्दगी में शातिरपने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया। खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं, उनकी सारी सम्पत्ति अपने यहाँ बैंकों में कैसे लाई जाए, और उन बैंकों से पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो नेपोलियन और हिटलर से लेकर पूरी दुनिया में दो ही तो थे, एक तो पश्चिम का जो पूँजीवाद जिसे हम बोलते हैं और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इन्हीं लोगों ने किया, दो व्यक्तियों ने। साम्यवाद को और जो पूँजीवाद दोनों को फाइनेंस किया, किसने?.... रोथशिल्ड और रॉकफेलर ने, और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई।"

बाद में बाबा रामदेव ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया। आजकल व्यवस्था परिवर्तन के हर मुद्दे पर बाबा रामदेव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्यों? क्या इन लोगों से बाबा डर गए या समझौता हो गया?

46
नोटबन्दी का खेल

अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए एवं भारत को एक गहरी आर्थिक मन्दी में धकेलने के लिए नोटबन्दी दरअसल बैंकर्स की ही एक सोची-समझी चाल है।

2008 में भारत के काले धन के आंकडे बाहर लाना इन्हीं बैंकर्स का ही एक षडयंत्र था। दुनिया को नियंत्रित करने वाले अंतराष्ट्रीय बैंकरो ने जब 2008 में विश्वस्तर पर मंदी लाने की कोशिश की तो अमेरिका तो इसकी चपेट में आ गया था पर भारत में गुप्त-धन होने से हम इस मंदी से अछूते रहे। यह बात दुनिया के शासको को पसंद नहीं आई और उन्होंने कालेधन का मुद्दा छिड़वा दिया। वो लोगों के गुप्त धन को बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करने वाला कोई बचे ही नहीं। पहले जन-धन योजना से बैंकों में खाते खुलवाना और अब सभी को बैंकों पर आश्रित करना उनकी एक सोची-समझी रणनीति है। अब भारत में मंदी और महँगाई के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना और आसान हो जाएगा क्योंकि अब इनको हर भारतीय की क्षमता पता चल जाएगी कि किसके पास, किस शहर में, लगभग कितना धन है। दूसरा, लोगों के पास जो भी सोना-चांदी इत्यादि रखा है उसको भी लूटने की तैयारी इनके द्वारा चल रही है। ये लोग पहले भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए एक बार कोशिश कर चुके पर असफल रहे, लेकिन जल्द ही ये किसी न किसी तरीके से देश के लोगो का सारा सोना-चांदी भी निकलवा लेंगे। साथ ही आने वाले समय में लोगो का सारा पैसा डिजिटल करके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा और कागज़ के नोट ही खत्म कर दिए जाएँगे। उस दिन भारत की गुलामी पक्की हो जायेगी और ये विदेशी ताकतें सदा-सदा के लिए भारत पर शासन स्थापित कर लेंगी। फिर जो कोई देशभक्त इन विदेशी जालिमों के विरुध्द आवाज उठाएगा, उसका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाएगा।

47

इकोनोमिक हिटमैन
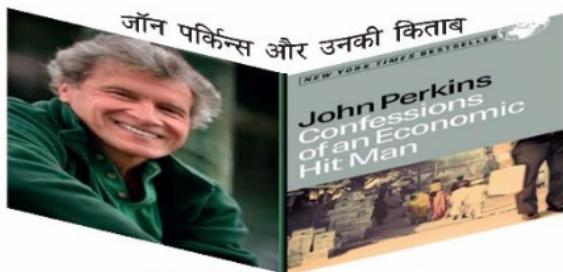
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एडम लिखते हैं, "किसी भी राष्ट्र को गुलाम बनाने के दो तरीके हैं। एक तलवार की धार से और दूसरा उसे कर्ज के जाल में फँसाकर"। इस कर्ज के जाल में गुलाम बनाने की प्रक्रिया को विश्व प्रसिद्ध लेखक जॉन पर्किन्स ने अपनी पुस्तक 'कंफेशन ऑफ एन इकोनोमिक हिटमैन' में समझाया हैं। जॉन पर्किन्स पहले इन्हीं लोगों के लिए काम करते थे परन्तु बाद में चेतना जागृत हुई तो जॉन ने इन लोगों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया। वे बताते हैं कि पहले संसाधन सम्पन्न किसी राष्ट्र को ढूँढा जाता है। फिर उसे विश्व बैंक या आई.एम.एफ. से विकास के नाम पर विशाल ऋण दिलाया जाता है। जबकि पैसा लोगों को नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण ऋण डॉलर में लिया जाता है, इसलिए ऋण और उसका ब्याज डॉलर में ही चुकाना होता है।

अगर कोई भी देश एक बार ऋणजाल में फँसा तो समझो स्वाहा। ऋण वापस नहीं चुकाया जाता तो वे जॉन पर्किन्स की तरह इकोनोमिक हिटमैन को भेजते हैं। उन देशों को ब्लैकमेल करते हैं।

इस तरह से उन देशों में सुधार के नाम पर कुछ शर्तें लगाकर वे पूरे देश के स्वामी बन जाते हैं।

उन शर्तों के अन्तर्गत वे उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन करने को कहेंगे, जिससे सस्ती दर पर देश के संसाधनों को लूटा जा सके। उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ से ये लोग सारे प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के भाव में ले जा रहे हैं। संसाधन ही असली धन हैं और अगर ये लुट गए तो देश को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा।

कुछ अन्य शर्तों में वे वैश्वीकरण के चक्रव्यूह में फँसाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट; एफ.डी.आई.) के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बैंक, बिजली प्रणाली, जल बोर्ड, बीमा कंपनियों को बेचने का दबाव बनाएँगे। वे यह भी चाहेंगे कि वह देश युद्ध में उनका साथ दे, उनके लिए अपने देश में उत्तर अटलांटिल सन्धि संगठन (नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन; नाटो) या अमेरिकी सेना के सैन्य अड्डे (मिलिटरी बेस) का निर्माण करे और संयुक्त राष्ट्र में मतदान में उनका साथ दें।

अगर कोई देश इन शर्तों को नहीं मानता है, तो वे लोग पर्किन्स की तरह हिटमैन भेजते हैं। इकनोमिक हिटमैन पहले उस देश के नेता को भ्रष्ट करके आर्थिक साम्राज्य के अधीन रहकर उनके इशारों पर काम करने के लिए कहेगा। अगर कोई नेता फिर भी ना माने तो उसे मारने के लिए लोग भेजे जाएँगे या देश की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जनता या सेना से तख्ता पलट करा दिया जाएगा। अगर देश की जनता और सेना नेता के साथ हों और वह बच जाए, तो फिर उस देश को बदनाम करके, युद्ध के माध्यम से अपना काम कर देंगे।

47
ईरान (1953) और ग्वाटेमाला (1954)

लोकतांत्रिक ढंग से मोसादेग ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। उनके कौशल को देखकर टाइम पत्रिका ने उन्हें 'मैन ऑफ द इयर' घोषित किया था। मोसादेग ने तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर ईरान के लोगों को लाभ पहुँचाने की घोषणा की। अमेरिका ने करोडों डॉलर के साथ सी.आई.ए. एजेंट कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान भेजा और ईरान में विद्रोह करवाया, मोसादेग सत्ता से फेंक दिए गए और कठपुतली के रूप में शाह को लाया गया। इस तरह से यह देशों में जोड़-तोड़ करके साम्राज्य बनाने का नया तरीका बन गया।

अरबेंज 1951 में उस समय ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने जब देश 'यूनाईटेड फ्रूट कम्पनी' की जकड़ में था। अरबेन्ज लोगों को उनकी जमीन वापस करना चाहते थे। यूनाईटेड फ्रूट कम्पनी ने अमेरिका के लोगों का मानस बनाने के लिए एक पब्लिक रिलेशन फर्म के माध्यम से अमेरिका में एक बड़ा अभियान छेड़ा कि अरबेंज रूस की कठपुतली है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है। अमेरिका ने अरबेंज को मारने के लिए एजेंट भेजे, विमान भेजे और अन्त में सेना ही भेज दी और अरबेन्ज को मार गिराया।

अरबेंज

चिले (1973)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.; कक्षा नौवीं) की लोकतांत्रिक राजनीति - 1 (दिसम्बर 2006) की पाठ्यपुस्तक, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से साम्राज्यवाद का विरोध करने पर चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे की हत्या कर दी गई।

1.1 लोकतंत्र के दो किस्से

राष्ट्रपति आयेंदे (हेलमेट में) और उनके सुरक्षा गार्ड चिले के राष्ट्रपति भवन ला मोनेदा के सामने। यह चित्र 11 सितम्बर 1973 का है और इसके कुछ घंटों बाद ही आयेंदे की हत्या कर दी गई। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या कहते हैं।

राष्ट्रपति आयेंदे बार-बार मजदूरों की बात क्यों करते हैं? अमीर लोग उनसे नाखुश क्यों थे?

"मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों! चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अँधियारें दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर-सबेर वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेगे। चिले जिंदाबाद! चिलेवासी जिंदाबाद! मजदूर जिंदाबाद!

ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा।"

ये सल्वाडोर आयेंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश, चिले, के राष्ट्रपति थे। यह भाषण

उन्होंने 11 सितंबर, 1973 की सुबह दिया था। और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया था। आयेंदे, चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने 'पॉपुलर यूनिटी' नामक गंठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयेंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बाँटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बाँटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनैतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से ताँबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियो को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनैतिक पार्टियाँ इन नीतियों के खिलाफ थीं।

1973 का सैनिक तख्तापलट

11 सितंबर 1973 को आयेंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुँचे

तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियों के माध्यम से घोषणाएँ की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इन्कार किया। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयेंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे।

11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्तो पिनोशे कर रहे थे।

अमेरिका की सरकार आयेंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्तापलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की माँग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इंकार किया था। जनरल बैशेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफी सारे लोग, 'लापता' हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ।

49

इक्वाडोर (1981)

जैम रोलदस

जैम रोलदस ने इक्वाडोर के संसाधनों को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करने का वायदा किया। यह सुनिश्चित करने के लिए वह चुनाव लड़ा और वह अब तक रिकोर्ड़ मतों से राष्ट्रपति बना। जॉन पर्किन्स ने उससे कहा, **"अगर तुम और तुम्हारा परिवार हमारे खेल खेलो तो ठीक है, तुम बहुत अमीर बन सकते हो। लेकिन अगर तुम वो नीति अपनाओगे जिसका वायदा जनता से किया था, तो माफ कीजिएगा... पर आपको मरना पड़ेगा!"**

एक विमान दुर्घटना में रोलदस की मृत्यु हो गई। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वैसे ही पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया और नज़दीक के एक सैनिक अड्डे से सिर्फ अमेरिकी सेना को वहाँ जाने की अनुमति थी। कुछ लोगों ने देखा की विमान से एक मिसाईल टकराई है उसके बाद ही वह गिरा है। इस बात की गवाही देने से पहले ही दो मुख्य गवाहों की भी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

50
पनामा (1981)
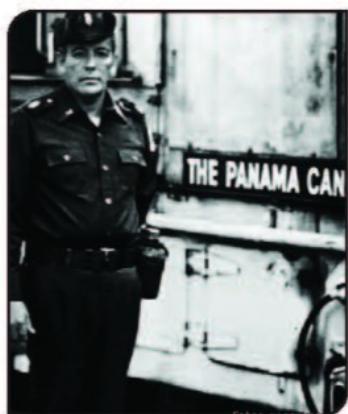
उमर टोरींजस

पनामा के राष्ट्रपति उमर टोरींजस बहुत करिश्माई व्यक्ति थे। वे वास्तव में अपने देश की मदद करना चाहते थे। जब जॉन पर्किन्स ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, **"देखो जॉन, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे देश के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका उस सारे विनाश की भरपाई करे जो उसने मेरे लोगों का किया है। मैं एक ऐसी स्थिति में होना चाहता हूँ जहाँ मैं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को उनकी स्वतंत्रता दिलाने और संयुक्त अमेरीका की इस भयानक उपस्थिति से मुक्त कराने में मदद कर सकूँ। आप हमारा बुरी तरह से शोषण कर रहे हो। मैं तो बस पनामा लोगों के हाथों में पनामा नहर वापस दिलाना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो।"**

1981 की मई में, जैम रोलदस की हत्या हो गई थी और उमर को इस के बारे में पता था। उमर टोरींजस ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, **"शायद अगला नम्बर मेरा है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जो करने के लिए यहाँ आया था वो कर दिया। मैंने पनमा नहर पर फिर से बातचीत की है। नहर अब हमारे हाथ में होगी।"** उसी वर्ष की जून में, दो महीने बाद, वे भी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। टोरींजस के सुरक्षा गार्ड ने अन्तिम क्षण में उसे एक टेप रिकॉर्डर सौंपा था जिसमें एक बम था।

51
वेनेजुएला (2002)

ह्यूगो शेवेज
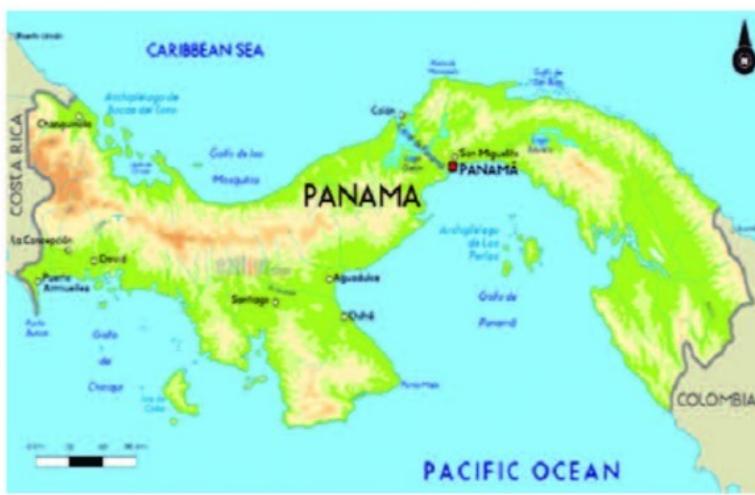
1998 में ह्यूगो शेवेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं और वो भी वेनेजुएला के तेल को मुख्य रूप से वेनेजुएला के लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने के वायदे के कारण। वेनेजुएला में 2002 में एक तख्तापलट की कोशिश की गई, जिसमें निश्चित ही सी.आई.ए. का हाथ था। विपक्ष ने कुछ हजार लोगों को प्रदर्शन करने भेजा और टेलिविज़न की मदद से इस भीड़ को ऐसा दिखाया गया कि लाखों लोग क्रान्ति चाहते हैं। फिर सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने शेवेज को बन्दी बना लिया। अमेरिका के पक्षधर सत्ता में आ गए और वे शेवेज को अमेरिका को सौंपने वाले थे। इस षड्यंत्र को समझकर अचानक शेवेज के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। अमेरिका के पक्षधर लोग भाग गए और शेवेज को मुक्त करा लिया गया। लोगों की ताकत के सामने अमेरिका भी टिक न पाया और शेवेज इस षड्यंत्र से बच गए।

सद्दाम हुसैन

52
ईराक (2003)

सद्दाम हुसैन एक समय पर सी.आई.ए. के ऐजेंट थे और अमेरीका ने ही उन्हें सत्ता में बैठाया था। पर उन्हें लगा कि वे भी शासक हैं और अमेरीका के लिए काम करना बन्द कर दिया। उन्हें इकोनोमिक हिटमैन ने पहले घूस देनी चाही पर वे नहीं माने। उन्हें मारने के लिए कुछ लोग भेजे गए, पर उनकी सुरक्षा मजबूत थी, इसलिए बच गए। उनका तख्तापलट करना चाहा, पर लोग और सेना उनके साथ थी। अमेरिका ने 1990 में ईराक में युद्ध छेड़ा पर जीत नहीं पाया।

सद्दाम ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर मुक्त व्यापार के लिए ईराक का तेल दूसरी मुद्राओं में देने की घोषणा की। इस कदम से अमेरीका पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। 2003 में रासायनिक हथियारों का भय दिखाकर सद्दाम को बदनाम करके युद्ध छेड़ा गया और अबकी बार जीत गए। 2005 में सद्दाम को फाँसी दे दी गई।

ईराक में युद्ध चलता रहे इसलिए ऐजेंटों की मदद से दोनों तरफ आर्थिक सहायता की जाती है। उदाहरण के तौर पर, 2005 में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ने अरब लोगों की पोशाक पहनकर लोगों पर खुले आम गोली चलाई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें बसरा शहर की जेल में रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने जब अपने दोनों अधिकारियों को छोड़ने को कहा तो बसरा सरकार ने मना कर दिया। ब्रिटिश सेना शहर में टैंक घुसाकर, जेल तोड़कर उन्हें छुड़ाकर ले गई।

53
समकालीन परिदृश्य

अमेरिकी जनरल वेसले क्लार्क ने 2007 के एक साक्षात्कार में बताया कि अमेरिका ने 2001 में 7 देश (ईराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, लीबिया, सोमालिया और सूडान) पर कब्ज़ा करने की रणनीति बनाई। इन सात देशों में एक समानता यह थी कि कोई भी देश बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का सदस्य नहीं था। इस तरह से उनकी बैंकिंग पर उनका कब्ज़ा नहीं था।

म्यांमार गद्दाफी

गद्दाफी के कार्यकाल में लीबिया में शिक्षा और चिकित्सा हर किसी के लिए मुफ्त थी। गाड़ी और तेल के दाम बहुत सस्ते थे और यहाँ तक कि नवविवाहित जोड़े को गुजर-बसर के लिए 60,000 दीनार (लगभग 32 लाख रुपए) मिलते थे। 2011 में लीबिया में गद्दाफी के विरुद्ध नाटो (NATO) सेना ने विद्रोहियों को हथियार देकर तख्ता पलट कराया, और पूरे विश्व में यह बताया गया कि गद्दाफी एक अय्याश आदमी था, जिसको मारकर अच्छा किया।

सूडान को भी दो हिस्सों में बाँटवा दिया। सीरिया, लेबनान, ईरान और सोमालिया में भी ये लोग अशान्ति फैला रहे हैं, क्योंकि ये सब देश इस्लामिक बैंकिंग के पक्षधर हैं और अपने तेल को डॉलर में नहीं बेचना चाहते। इससे अमेरिका बर्बाद हो सकता है।

54
मानसिक गुलामी

ये लोग दुनिया के लगभग सभी देशों, राजनीति, उद्योग, व्यापार, मीडिया, तेल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, ऐतिहासिक तथ्यों और यहाँ तक कि हमारे मानस, सोच और आन्दोलनों तक को नियंत्रित करते हैं।
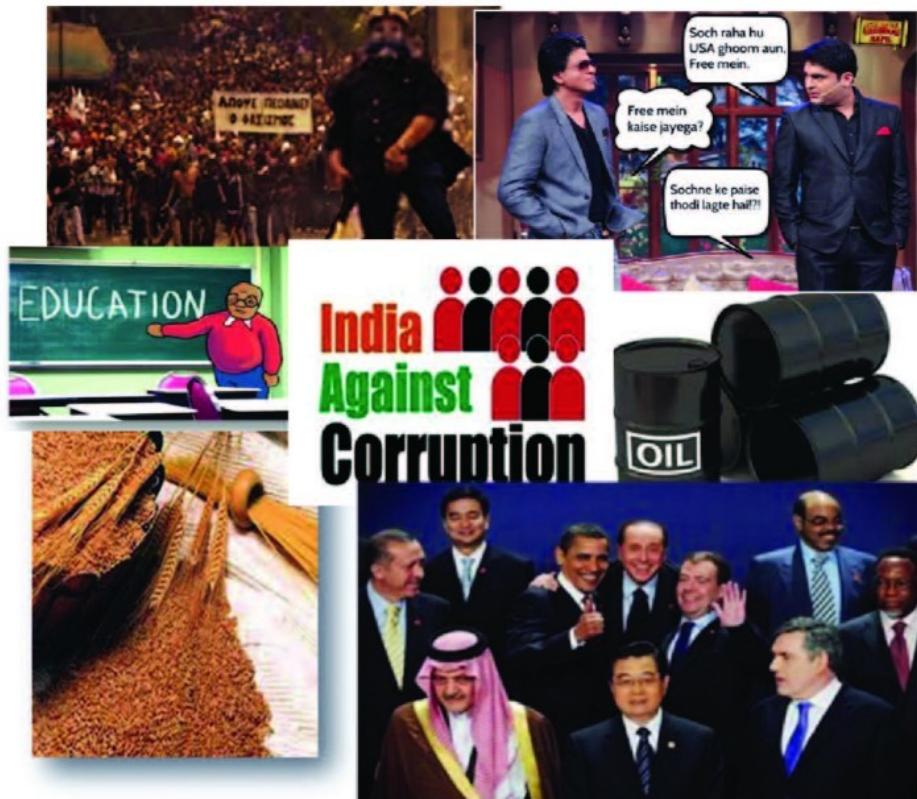
ये लोग नहीं चाहते कि हम कुछ ज़्यादा सोचें, इसलिए शराब, ड्रग्स, टेलीविजन, मिडिया और हर तरह के वे साधन जो हमें मनोरंजन में व्यस्त रखें, हमारे लिए उपलब्ध कराए जाते हैं; ताकि हम ज़्यादा सोचकर महत्वपूर्ण लोगों के रास्ते का रोड़ा न बनें। बेहतर होगा कि आप लोग जाग जाएँ और देखें की कुछ लोग आपके जीवन को नियंत्रित कर रहें हैं और आपको पता तक नहीं।

55

परम उद्देश्य - एक विश्व सरकार

अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए वे लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का व्यवधान सामने आए। इसलिए वे चाहते हैं कि विश्व में एक सरकार, एक सेना, एक भाषा, एक करेंसी और एक बैंक बने।

जेम्स वारबर्ग, वारबर्ग बैंकिंग परिवार के एक सदस्य, लिखते हैं, **"तुम इसे पसन्द करो या नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सरकार विजय से बनेगी या सहमति के द्वारा।"**

डेविड रॉकफेलर का मानना है, **"हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश विश्व की नई व्यवस्था स्वीकार कर लेंगें।"**

56
समाधान

क्या मात्र राजनैतिक सत्ता परिवर्तन करके, व्यवस्था परिवर्तन किए बिना किसी तरह का बदलाव लाना सम्भव है? जबकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था के मूल में अर्थव्यवस्था ही होती है। व्यवस्था के पिरामिड में बैंकिंग व्यवस्था को बदले बिना, क्या किसी भी तरह का समाधान सम्भव है?

सर जोशिया स्टांप

समाधान के तौर पर सर जोशिया स्टांप, बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक और 1920 में ब्रिटेन में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का टेक्सास विश्वविद्यालय में 1927 का भाषण, **"आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जादुई तरीके से पैसा बनाती है। यह प्रक्रिया शायद जादू का अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। बैंकिंग की कल्पना में अन्याय है और यह पाप में जन्मी है। बैंकर्स पृथ्वी के मालिक हैं। अगर इसे तुम उनसे छीन भी लो पर उन्हें पैसे बनाने की शक्ति देकर रखो तो वे कलम के एक झटके के साथ, धरती को फिर से वापस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बना लेंगे। उनसे यह महान शक्ति छीन लो फिर यह दुनिया ज़्यादा खुशहाल और रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी। परन्तु अगर आप बैंकरों के गुलाम बने रहना चाहते हो और अपनी खुद की ही गुलामी की लागत का भुगतान जारी रखना चाहते हो, तो बैंकरों को पैसे बनाने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति देकर रखो।"**

57

गरंसी का अनुभव

गरंसी ब्रिटिश चेनल में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। 1816 में गरंसी पर 19,000 पाउंड का कर्ज था और आय 3,000 पाउंड थी, जिसमें से 2,400 कर्ज उतारने में चली जाती थी। बेरोजगारी के कारण लोग द्वीप छोड़कर जाने लगे थे। फिर सरकार ने 6,000 पाउंड के कर्जमुक्त नोट छापे और सबको रोजगार मिलने लगा। फिर 1820 में 4,500 पाउंड; 1821 में 10,000; 1824 में 5,000 पाउंड; 1826 में 20,000 पाउंड और 1837 में 50,000 पाउंड जारी किए। 1914 में गरंसी ने 1,42,000 पाउंड की योजना अगले 4 साल के लिए बनाई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गरंसी ने 1958 तक कुल 5,42,000 पाउंड जारी किए थे। पिछले 200 साल में पैसे कि मात्रा 25 गुना हो गई, पर महँगाई का दूर-दूर तक पता नहीं चला।

आज 44,600 डॉलर की सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ गरंसी विश्व में 11वें स्थान पर है। जबकि भारत एक विशाल राष्ट्र होने के बावजूद 4,000 डॉलर की सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ 141वें स्थान पर है।

58

लेंगे हम पाँच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम

हम चाहते हैं की भारत की संसद में एक बिल पास हो, जिसके अन्तर्गत इन पाँच बिन्दुओं को रखा जाए :

1. भारत सरकार देश के लिए कर्जमुक्त पैसा बनाए/जारी करे, न कि व्यावसायिक बैंक या केन्द्रीय बैंक।
2. अंश रिजर्व बैंकिंग प्रणाली को 100 प्रतिशत रिजर्व बैंकिंग बनाया जाए।
3. सट्टाबाजारी (derivatives) पूरी तरह से बन्द हों।
4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर मुक्त करके भारत को अमेरीका से मुक्त कराएँ।
5. अँग्रेजों के बनाए सारे काले कानून हटाए जाएँ।

नोट : समाधान हेतु पाँच बिन्दुओं को विस्तार से अगली पुस्तक में समझाया गया है।

59
भविष्य का भारत और रणनीति

बर्बादी की ओर बढ़ते भारत में यह कानून बनते ही भारत की तस्वीर बदल जाएगी और देश में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेंगे

- महँगाई मुक्त, मंदी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, गरीबी मुक्त, कर्ज मुक्त, कर मुक्त भारत।
- व्यापारी, किसान कर्जमुक्त हो जाएँगे और तरक्की करेंगें।
- युवाओं को निश्चित रोजगार मिलेगा।
- समृद्ध और सुखी भारत।
- स्वतंत्र और स्वावलम्बी भारत।
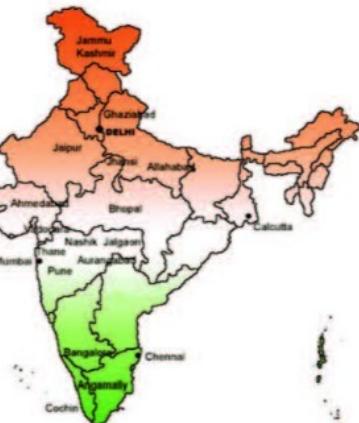
अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी ईमानदार न्यायधीश है...

सुप्रीम कोर्ट इस पूरी व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के विरुद्ध है और हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करती है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत देश का सर्वोच्च न्यायलय स्वयं निर्णय लेकर इसके विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है।

संसद भी यह कानून बना सकती है पर संसद इन्हीं लोगों से संचालित है, इसलिए संसद पर दबाव बनाने के लिए जोरदार आन्दोलन की ज़रूरत है।

60

सीधी बात

साथियों सीधी बात यह है कि परिवर्तन बिना किए तो होगा नहीं और बाहर से करने कोई आयेगा नहीं, तो कुल मिलाकर हमें ही कुछ करना होगा। बिना संगठन के बनाए तो लड़ाई जीतने से रहे और संगठन बनाने के लिए चाहिए संगठन में पूरा जीवन लगाने के लिए कुछ देशभक्त लोग।

अब देशभक्तों को भी अभियान को बढ़ाने के लिए चाहिए होगा - साधन। देश की आजादी के लिए साधन जुटाने के दो रास्ते हैं या तो भगतसिंह और उनके साथियों की तरह करें 'काकोरी जैसी लूट' और पकड़े जाने पर अभियान खत्म या फिर देश के प्रति लोग ही अपनी जिम्मेदारी समझें और देश की आजादी के लिए आर्थिक सहायता करें।
दूसरा विकल्प ज्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें अहिंसक तरीके से ताकत बनाकर जीत की ज्यादा संभावनाएँ हैं और कोई रास्ता देश को आजाद कराने के लिए आपके पास हो तो जरुर बताएँ।

समय निकलता जा रहा है अभी कुछ नहीं किया तो फिर बाद में बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अभी शुरूआत करेंगे तो ही पांच-सात साल में एक संगठित ताकत बन पायेगी। अब फैसला आपके हाथ में है और आपको ही तय करना है कि आपका क्या योगदान रहेगा।

क्रान्तिकारियों का सपना पूरा करने और देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ लोग तो पूरा जीवन हमारे साथ इसी कार्य के लिए समर्पित करें और बाकी सभी लोग

100☐ 200☐ 500☐ 1000☐

रु. महीने का योगदान अवश्य करें।

युवा क्रान्ति

E-mail : yuvakranti.org@gmail.com | Web : www.yuvakranti.org
: www.fb.com/yuvakranti.org : twitter.com/yuvakrantikari
M. : 08745026277

नोट - आप इस पुस्तक को **bankjaal.com** से निशुःल्क पढ़ सकते हैं।

सन्दर्भ सूची

- इंगदाल, एफ.; विलियम, ए सेंचुरी ऑफ वार - एंग्लो-अमेरिकन ऑइल पॉलिटिक्स एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर; प्रोग्रेसिव प्रेस, केलीफोर्निया; 2012
- ग्रिफिन, जी. एडवर्ड; द क्रिएचर फ्रॉम जैकल आइलैंड; अमेरिकन मीडिया, केलीफोर्निया; 1998
- नौरोजी, दादाभाई; पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया; कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, दिल्ली; 1901
- पर्किंस, जॉन; कंफेशन ऑफ एन इकॉनोमिक हिटमैन; बैरेट-कोएह्लर पब्लिशर्स; सेन फ्रांसिको, 2004
- पर्किंस, जॉन; द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन एंपायर; पेंगुइन ग्रुप, न्यू यॉर्क; 2009
- फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ शिकागो; मॉर्डन मनी मेकेनिक्स - अ वर्कबुक ऑन बैंक रिज़र्व्स एंड डिपॉज़िट एक्सपेंशन; 1911
- ब्राउन, एलन हॉड्जसन; द पब्लिक बैंक सॉल्यूशन - फ्रॉम ऑस्टेरिटी टू प्रॉस्पेरिटी; थर्ड मिलेनियम प्रेस, लॉस एजेंलिस; 2013
- ब्राउन, एलन हॉड्जसन; वेब ऑफ डेट - द शॉकिंग ट्रुथ अबाउट अवर मनी सिस्टम एंड हाउ वी कैन ब्रेक फ्री; थर्ड मिलेनियम प्रेस, लॉस एजेंलिस; 2012
- भारत का संविधान; इस्टर्न बुक कम्पनी, नई दिल्ली; 2011
- भारत का संविधान; भारत सरकार का वेब पोर्टल (http://india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (www.rbi.org)
- लिएटर, बर्नार्ड; द फ्यूचर ऑफ मनी; रेंडम हाउस, न्यू यॉर्क; 2013,
- सटन, सी. एंटोनी; वॉल स्ट्रीट एंड द बोल्शेविक रिवोल्यूशन; क्लेअरव्यू बुक्स; ससेक्स 2011
- सामाजिक विज्ञान लोकतातंत्रिक राजनीति 1; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली; 2006

दरिद्रता के समस्त स्त्रोतों को समृद्धि के स्त्रोत मानना और समष्टि हित पर पानी फेरने की भावना को क्रियान्वित करना आर्थिक विपन्नता का मुख्य हेतु है। इस सन्दर्भ में रवि कोहाड़ द्वारा विरचित 'बैंकों का मायाजाल' का अध्ययन और अनुशीलन सुमंगल है।

– निश्चलानन्द सरस्वती
श्री जगत् गुरू शंकराचार्य, पुरी पीठ

वर्तमान बैंकिंग प्रणाली धर्म और संस्कृति के विरुद्ध खड़ी है। भारतीय मुद्रा को कर्जमुक्त बनाते हुए इस पर गाय का चित्र अंकित होना चाहिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था लानी होगी। इस विषय में यह पुस्तक अवश्य पढ़ें।

– राष्ट्रहित चिंतक
जैन आचार्यश्री

देश के बैंकों का सच जानना है तो यह किताब पढ़ना जरूरी है। विशेषता: देश के युवाओं को पढ़ना आवश्यक है।

– अन्ना हजारे

करंसी को करंसी से हराने के हर प्रयत्न असफल हुए हैं, इसका इतिहास इस किताब से मिलेगा। करंसी को जीवनपद्धत्ति से बदलने की कोई बात बन सकती है? युवा क्रान्ति के एक-रस तरुणों को, संगठक श्री अक्षय कुमार को तथा विशेष रूप से इस किताब के लेखक श्री रवि कोहाड़ को हार्दिक आशीर्वाद है।

–प्रवीणा देसाई
ब्रह्म विद्या मन्दिर, पवनार, वर्धा

पारह न. 3, सूरत अल-बक़रह, आयत 275 –कुरान शरीफ़

"अल्लाह ने हलाल किया खरीदो –फ़रोख्त को और हराम किया सूद (ब्याज) को !" मुसलमानों, अल्लाह का हुक्म है और उसके नबी की हिदायत है कि इस्लाम में ब्याज का लेनदेन हराम है। पर आज लगभग सभी लोग इस ब्याज के जाल में फँसे हुए हैं और जाने – अनजाने में सूदखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसकी वजह से हमारा ईमान और समाज दोनों ही बर्बादी के मुहाने पर हैं। ये कैसे है और क्यों है, ये समझने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें।

– नोमान जमाल
सामाजिक कार्यकर्ता संगठन

मूल्य : अनमोल
सहयोग राशि : श्रद्धानुसार